Useful For Prelims

Date: 18 December 2025

# भारत-इथियोपिया क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा के मामले में स्वाभाविक साझेदार हैं : मोदी

प्रधानमंत्री मोदी को मिला इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान।

**जनसत्ता ब्यूरो**
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इथियोपियाई संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपर्क के मामले में स्वाभाविक साझेदार हैं।

मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश एक ऐसी दुनिया के लिए कार्यरत हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक समानता मूलक और अधिक शांतिपूर्ण हो। अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर इथियोपिया पहुंचे मोदी ने कहा कि शेरों की भूमि इथियोपिया में आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है।उन्होंने स्थानीय भाषा में सांसदों का अभिवादन करते हुए कहा, 'तेना यिस्टिलिगन, सलाम'। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे यहां घर जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों की भूमि है।

-पूरी खबर पेज 16

Jansatta Page No-1

# विपक्ष के विरोध के बीच जी राम जी विधेयक पेश

## प्रतिपक्ष ने कहा-यह गरीब, किसान और मजदूर विरोधी सोच को दर्शाता है

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी विरोध के बीच लोकसभा में 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' पर बुधवार को चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को धीरे-धीरे कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाकर नया विधेयक लाना सरकार की 'गरीब, किसान और मजदूर विरोधी सोच' को दर्शाता है।

तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रपिता का नाम हटाकर उनके रामराज्य से जुड़े विचारों को नष्ट करने की बात कही। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि इस विधेयक को देश में रामराज्य लाने और महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए लाया गया है।

लोकसभा में 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने नए कानून में राज्यों के 40 फीसद अंशदान वाले प्रावधान का उल्लेख किया और कहा कि सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तरह राज्यों पर 10 फीसद भार ही रखना चाहिए। इससे पहले, विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक विकसित भारत के लिए विकसित गांवों के निर्माण का विधेयक है, जिसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी 125 दिन की कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के स्थान पर लाया गया यह विधेयक केवल रोजगार का विधेयक नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी के स्वावलंबी और रोजगारयुक्त गांव बनाने के सपनों का विधेयक है।

चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि 2005 में मनरेगा कानून आया था तो उस समय विपक्ष में रही भाजपा की मांग को मानते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे संसदीय समिति को भेजने पर सहमति जताई थी तथा सभी दलों के नेताओं के विचार-विमर्श के बाद इसे सदन में लाया गया। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि जब 2005 में विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया था, तो अब इसे संसदीय समिति को भेजने की मांग को क्यों नहीं माना जा रहा।

उन्होंने अधिनियम का नाम बदलने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि (अधिनियम से) महात्मा गांधी का नाम हटाना इस देश में सबसे बड़ा अपराध है। जयप्रकाश ने कहा कि इस सरकार को या तो महात्मा गांधी के नाम से परेशानी है या गांधी उपनाम से परेशानी है? वो तो मंत्री बताएंगे। जयप्रकाश ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये लोग बाकी पेज ८ पर

*कांग्रेस* ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को धीरे-धीरे कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाकर नया विधेयक लाना सरकार की 'गरीब, किसान और मजदूर विरोधी सोच' को दर्शाता है। *ग्रामीण* विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के स्थान पर लाया गया यह विधेयक केवल रोजगार का विधेयक नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी के स्वावलंबी और रोजगारयुक्त गांव बनाने के सपनों का विधेयक है।

फाइल फोटो

Jansatta Page No-1

---

वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन की किताब में उल्लेख | संस्मरण | अटल का मत था कि उन्हें राष्ट्रपति बनाना अच्छा संकेत नहीं होगा

# वाजपेयी ने खुद को राष्ट्रपति बनाने का सुझाव किया था खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर विचार करने से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर से यह सुझाव आया था कि अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लें तथा प्रधानमंत्री पद लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दें। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इससे इनकार करते हुए कहा था, कि बहुमत के बल पर उनका राष्ट्रपति बनना एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी।

प्रधानमंत्री वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने 'प्रभात प्रकाशन' की ओर से प्रकाशित पुस्तक 'अटल संस्मरण' में इस प्रकरण का उल्लेख किया है।

अब्दुल कलाम 2002 में केंद्र के तत्कालीन सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्ष दोनों के समर्थन से 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वे 2007 तक इस पद पर रहे।

टंडन ने अपनी पुस्तक में बताया है कि कलाम के नाम पर विचार से पहले कैसे भाजपा के भीतर से ही यह सुझाव आया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी को राष्ट्रपति भवन भेजा जाए। वे लिखते हैं कि डाक्टर पीसी अलेक्जेंडर महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक प्रभावशाली साथी व्यक्तिगत तौर पर अलेक्जेंडर के संपर्क में थे। उन्हें ऐसा संकेत दे रहे थे जैसे वे वाजपेयी के दूत हों। वे सज्जन वाजपेयी को लगातार यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अलेक्जेंडर, जो कि एक ईसाई हैं, को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहिए। ऐसा करने से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी असहज होंगी और भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि देश में एक ईसाई राष्ट्रपति के रहते एक और ईसाई प्रधानमंत्री नहीं हो सकेगा।

उनका कहना है कि दूसरी ओर, तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत राजग के संयोजक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू व अन्य नेताओं पर अपनी उम्मीदवारी के लिए निर्भर थे। टंडन ने लिखा है, इसी दौरान भाजपा के भीतर से स्वर उठने लगे कि क्यों न अपने ही दल से किसी वरिष्ठ नेता को इस पद के लिए चुना जाए।

टंडन के अनुसार, इस बीच पूरा विपक्ष सेवानिवृत्त हो रहे राष्ट्रपति केआर नारायणन को राजग उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। नारायणन की शर्त थी कि वे तब ही चुनाव लड़ने को तैयार होंगे, जब निर्विरोध चुने जा सकेंगे। वर्ष 1998 से 2004 तक वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे टंडन ने लिखा है, कि वाजपेयी ने अपने दल के भीतर से आ रहे उन सुझावों को सिरे से खारिज कर दिया कि वे स्वयं राष्ट्रपति भवन चले जाएं और प्रधानमंत्री पद अपने नंबर दो नेता लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दें। टंडन के अनुसार, वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं थे।

उनका मत था कि किसी लोकप्रिय प्रधानमंत्री का बहुमत के बल पर राष्ट्रपति बनना भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। यह एक बहुत गलत परंपरा की शुरुआत होगी और वे ऐसे किसी कदम का समर्थन करने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे। टंडन के मुताबिक, वाजपेयी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया, ताकि राष्ट्रपति पद के लिए आम सहमति बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह उनसे मिलने आए थे। वाजपेयी ने पहली बार आधिकारिक रूप से खुलासा किया कि राजग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बनाने बाकी पेज ८ पर

Jansatta Page No-1

---

'अटल संस्मरण'

# राष्ट्रपति न बनकर अटलजी ने पेश की थी राजनीतिक शुचिता की मिसाल

**वाजपेयी ने कहा था- मैं लोकप्रिय पीएम हूं, मेरे पास बहुमत है, ऐसे में लोकतंत्र में गलत संदेश जाएगा, पूर्व पीएम के मीडिया सलाहकार अशोक टंडन की किताब में पहली बार सामने आई यह बात, कलाम की जगह अटल को देश का 11वां राष्ट्रपति बनाने का भाजपा में आया था प्रस्ताव**

**नई दिल्ली, एजेंसी:** डा. एपीजे अब्दुल कलाम की जगह राष्ट्रपति न बनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीतिक शुचिता की मिसाल पेश की थी। ऐसी नजीर शायद ही कभी देखने को मिले। यदि वाजपेयी ने भाजपा में उनके लिए आया देश का शीर्ष संवैधानिक पद संभालने का प्रस्ताव मान लिया होता तो साल 2002 में अटल देश के 11वें राष्ट्रपति होते और उनके उत्तराधिकारी लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री। हालांकि, बाजपेयी ने इस सुझाव को ठुकराते हुए कहा था कि उनका बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति बनना एक गलत मिसाल स्थापित करेगा। अटलजी का यह त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण दर्शाता है कि यदि नेता ईमानदारी दिखाते हुए आदर्शों पर चले तो राष्ट्र और संगठन दोनों को कामयाबी मिलना तय है।

इस बात का राजफाश 1998 से 2004 तक बाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने अपनी किताब 'अटल संस्मरण' में किया है। कलाम को 2002 में तत्कालीन सत्तारूढ़ राजग और विपक्ष के समर्थन से राष्ट्रपति चुना गया था। वे 2007 तक इस पद पर रहे। टंडन ने लिखा- 'वाजपेयी ने स्पष्ट रूप से इस सुझाव को ठुकरा दिया कि उन्हें राष्ट्रपति भवन जाना चाहिए और आडवाणी को प्रधानमंत्री पद सौंप देना चाहिए जो कि उनके सेकेंड-इन-कमांड थे। टंडन के अनुसार, "वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मैं लोकप्रिय पीएम हूं। मेरे पास बहुमत है। किसी भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति बनना भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। यह एक बहुत गलत मिसाल स्थापित करेगा और वह ऐसे कदम का समर्थन करने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे।"

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। फाइल

टंडन ने लिखा है कि बाजपेयी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया ताकि राष्ट्रपति पद के लिए सहमति बनाई जा सके। उन्होंने लिखा- "मुझे याद है कि सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी और डा. मनमोहन सिंह उनसे मिलने आए थे। बाजपेयी ने पहली बार आधिकारिक रूप से बताया कि एनडीए ने डा. एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नामित करने का निर्णय लिया है। बैठक में एक दम सन्नाटा छा गया। फिर सोनिया ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आपके चयन से हम स्तब्ध हैं और हमारे पास कलाम को समर्थन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

वाजपेयी-आडवाणी की जोड़ी राजनीति में सहयोग और संतुलन का प्रतीक पेज>>5

********

### गडकरी बोले, मतभेद हों, मनभेद नहीं, यह राजनीतिक मंत्र है "अटल"

नई दिल्ली : केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के विचार कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उनका व्यक्तिगत आचरण राजनेता के तौर पर आदर्श है। उनका मूल सिद्धांत था- मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं। विचारों में भिन्नता हो सकती है, पर मन में भेद नहीं होना चाहिए। गडकरी ने बुधवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन की किताब 'अटल संस्मरण' के विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। (पेज-6)

Dainik Jagaran Page No-1

# सिकुड़ रहा गंगोत्री ग्लेशियर, 60 साल में 36 किमी हुआ कम

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून

- 13 से 14 हजार फीट ऊंचाई वाली चोटियों पर तापमान में सबसे तेज वृद्धि दर्ज
- डीबीएस महाविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग ने गंगोत्री ग्लेशियर पर किया अध्ययन

दून के डीबीएस महाविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग ने गंगोत्री ग्लेशियर के साल दर साल सिकुड़ने पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 60 वर्ष में गंगोत्री ग्लेशियर 36 किलोमीटर तक सिकुड़ गया है। यानी इसका धनत्व 36 किमी कम हो गया है। ग्लेशियर के सिमटने का कारण वैश्विक तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग), अवैज्ञानिक निर्माण, नदी घाटियों में खनन, जंगलों की कटाई, बसावट वाले क्षेत्रों में लगातार विस्तार को माना गया है। ग्लेशियर की सेहत सबसे ज्यादा खराब होने की वजह मौसमी चक्र में बदलाव है यानी जहां पहले बर्फ पड़ती थी, अब वहां बारिश हो रही है। यही नहीं, हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हो रही है।

महाविद्यालय के भूगर्भ विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दीपक भट्ट के अनुसार उत्तरकाशी की पांच अगस्त की धराली आपदा का एक बड़ा कारण ग्लेशियर का सिकुड़ना और बर्फ विहीन चोटियों का कमजोर पड़ना भी रहा है। वर्ष 1960 तक गंगोत्री ग्लेशियर की अंतिम टेल (पूंछ) धराली तक फैली हुई थी, लेकिन वर्ष 2025 आते-आते ग्लेशियर लगभग 36 किमी कम होकर गोमुख क्षेत्र के आसपास सिमट गया है। यही नहीं, 13 से 14 हजार फीट ऊंचाई वाली चोटियों पर तापमान में तेज वृद्धि दर्ज की जा रही है। गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार के कारण यहां से निकलने वाली गंगा समेत अन्य नदियों के जल स्तर में भी पिछले 60 वर्ष में 15 से 20 प्रतिशत की कमी भी आई है। डीबीएस कालेज, देहरादून के भूगर्भ विज्ञान विभागाध्यक्ष डा. दीपक भट्ट ने इस वर्ष धराली (उत्तरकाशी) आपदा के बाद से गंगोत्री ग्लेशियर पर अध्ययन कर रहे हैं। विभाग हर छह महीने में अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर रहा हैं।

गंगोत्री ग्लेशियर का निचला मुहाना जिसे लोग गौमुख के नाम से जानते हैं। इंटरनेट मीडिया

**राज्य के अन्य ग्लेशियर भी हो रहे प्रभावित :** उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के अलावा पिंडारी, मिलम, खतलिंग, बागिनी, कफनी, सुंदरढूंगा, रालम और नामिक जैसे प्रमुख ग्लेशियरों पर भी ग्लोबल वार्मिंग से अछूते नहीं हैं। प्रो. दीपक भट्ट कहते हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि नदी घाटियों में खनन, जंगलों के साथ शहरीकरण से ग्लेशियर प्रभावित हैं।

Dainik Jagaran Page No-14

## रिचर्ड वाकर ने खोजा शनि का चंद्रमा एपिमेथियस

1966 में आज ही अमेरिका में रिचर्ड वाकर ने शनि के चंद्रमा एपिमेथियस की खोज की थी। शनि के 150 चंद्रमाओं में से एक एपिमेथियस अपनी कक्षा को अन्य चंद्रमा जानूस के साथ साझा करता है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है।

## विश्व का पहला संचार उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया गया

1958 में आज ही नासा ने विश्व का पहला संचार उपग्रह सिग्नल कम्युनिकेशन बाय आर्बिटिंग रिले इक्विपमेंट (स्कोर) को कक्षा में प्रक्षेपित किया था। इसने राष्ट्रपति आइजनहावर के क्रिसमस संदेश का प्रसारण कर साबित किया कि उपग्रह संदेशों को रिले कर सकते हैं।

Dainik Jagaran Page No-14

## भारतीय फोटो पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं टीएस सत्यन

टीएस सत्यन का जन्म 1923 में आज ही मैसुरु में हुआ था। स्कूली जीवन में ही फोटोग्राफी के प्रति रुचि जगी। 1948 में अंग्रेजी अखबार में फोटोग्राफर के रूप में जुड़े। 1954 में पुडुचेरी का भारत संघ में विलय, 1964 में पोप पाल 6 की भारत यात्रा सहित कई ऐतिहासिक घटनाओं को कवर किया। डब्ल्यूएचओ की कई परियोजनाओं के लिए भी काम किया। उन्होंने भारत के बदलते परिदृश्य, आम लोगों के जीवन और आजादी के बाद के संघर्षों को अपनी मानवतावादी तस्वीरों के माध्यम से विश्वभर में पहुंचाया, जिससे भारतीय फोटो पत्रकारिता की नींव पड़ी।

Dainik Jagaran Page No-14

दैनिक जागरण
सप्तरंग
तकनीक की दुनिया का



गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025

उपलब्धियां 2025

# एआइ से कितनी बदली दुनिया



• फोटो फ्रीपिक

**नए टूल्स और खूबियों के साथ इस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां अधिक परिपक्व हुआ, तो वहीं इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग तेजी से बढ़ा है। तकनीक की दुनिया में क्या रहा खास और क्या हैं उम्मीदें, चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र...**

हर वर्ष तकनीक की दुनिया में कुछ ऐसी परिवर्तनकारी उपलब्धियां दर्ज होती हैं, जो उस साल की पहचान के साथ जुड़ जाती हैं। साल 2025 में जेनरेटिव एआइ एजेंट्स से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक और कामर्शियल रोबोटैक्सी से लेकर एनर्जी स्टोरेज तक बड़े बदलाव चर्चा में रहे। एआइ और वैज्ञानिक नवाचार स्वास्थ्य, पर्यावरण, अंतरिक्ष जैसे अनेकानेक क्षेत्रों में नई संभावनाओं की दिशा तय कर रहे हैं। खासकर, बीमारियों के प्रभावी उपचार, नई दवाओं की खोज, नए उपकरणों से सहजता बढ़ाने और इमरजेंसी सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ये हमारे दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।

**जेनरेटिव एआइ : असिस्टेंट से अब एआइ एजेंट** : जेनरेटिव एआइ अब एजेंटिक एआइ के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। एआइ इंटरकनेक्टेड एजेंट के तौर पर अब स्वतः स्पेशलाइज्ड टास्क करने में सक्षम होने जा रहे हैं। रीजनिंग क्षमताओं में सुधार के चलते एआइ माडल साक्ष्य आधारित आउटपुट के साथ-साथ बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्रिडिक्टिव मेंटिनेंस और सप्लाई चेन जैसे जटिल कार्यों को करने में सक्षम बनेंगे। वे खुद निर्णय लेकर अब आउटपुट दे रहे हैं, साल 2025 इस मामले में मील का एक पत्थर रहा है। आने वाले वर्षों में हम सुपरएजेंट को विकसित होते हुए देखेंगे, जिससे हेल्थकेयर, ला और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी इंडस्ट्री के लिए नए तरह का एआइ इकोसिस्टम तैयार होगा।

**बदल रही है कंटेंट क्रिएशन की दुनिया** : कंटेंट क्रिएशन में एआइ के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पारंपरिक साफ्टवेयर कंपनियों के समक्ष नई चुनौती खड़ी हो गई है। एआइ-फर्स्ट प्लेटफार्म टेक्स्ट-टू-इमेज जैसी सुविधाएं आफर कर रहे हैं, यानी आप कुछ शब्द टाइप कर कोई भी इमेज बना सकते हैं। फोटोशाप में पहले जेनरेटिव फिल और इमेज एक्सपेंशन जैसे फीचर्स जोड़े गए थे, लेकिन 2025 में यूजर एप के अंदर ही पूरी इमेज तैयार करने लगे। एडोब का फायरफ्लाई एक ऐसा ही इमेज जेनरेशन टूल है जो कापीराइट की चिंताओं से मुक्त होकर बेहतर इमेज तैयार करने की सुविधा देता है। वहीं चैटजीपीटी में बिल्ट-इन इमेज क्रिएशन और एडिटिंग टूल्स की सुविधा मिल रही है, जिससे विजुअल्स, फोटो को केवल टेक्स्ट प्रांप्ट के जरिये मोडिफाई किया जा सकता है। इसी तरह गूगल के जेमिनी 'नैनो बनाना' माडल आकर्षक फोटो बनाने की अपनी बेहतर खूबियों के चलते इस वर्ष काफी लोकप्रिय हुआ। यूट्यूब ने भी 2025 में वीओ2 फीचर की घोषणा की, जो टेक्स्ट प्रांप्ट से वीडियो बनाने में मदद करता है।

**साइबर सुरक्षा : नए खतरे और सुरक्षा के नए तरीके** : अनेक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि बीते एक साल में जेनरेटिव एआइ के इस्तेमाल से सुरक्षा में सेंध या सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं या कहें 2025 में साइबर सिक्योरिटी में जेनरेटिव एआइ सबसे चर्चित टापिक रहा। एंडप्वाइंट और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए निवेश और नवाचार में वृद्धि हो रही है। एआइ के जरिये वाइस क्लोनिंग, डीपफेक वीडियो के मामले आए दिन चर्चा में रहते हैं, उसे देखते हुए ना केवल साइबर सुरक्षा कंपनियों, बल्कि सामान्य यूजर्स को अब अधिक जागरूक होने की जरूरत है। हालांकि, साइबर सुरक्षा में एआइ आधारित थ्रेट इंटेलिजेंस के माध्यम से आटोमेटिक थ्रेट डिटेक्शन साइबर सुरक्षा को बेहतर बना रहा है। एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को अधिक सुरक्षित बनाने में एआइ टूल्स किस तरह उपयोगी साबित हो सकते हैं, इस दिशा में प्रयास बढ़ता दिखेगा। कुल मिलाकर, एआइ ने तकनीक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक चिंताओं को भी बढ़ा दिया है।

**कंप्यूटिंग और कनेक्टिविटी** : क्वांटम कंप्यूटिंग अब सैद्धांतिक शोध से बाहर निकल वास्तविक दुनिया में बदलाव लाने के लिए तैयार हो रही है। गूगल का 'विलो' क्वांटम चिप और माइक्रोसाफ्ट व एटम कंप्यूटिंग द्वारा इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिससे पारंपरिक सुपरकंप्यूटर्स के मुकाबले फ्यूचर कंप्यूटिंग कहीं अधिक तीव्र और उपयोगी साबित होगी। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट 6जी तीव्र विकास के चरण में है, जो प्रति सेकंड टेराबाइट और माइक्रोसेकंड लेटेंसी को सपोर्ट करेगा। इससे आटोनामस सिस्टम अधिक हाइपर कनेक्टेड होगा और इंटरनेट आफ थिंग्स (आइओटी) में व्यापक बदलाव आएगा।

## इन क्षेत्रों में एआइ का बढ़ता प्रभाव

### हेल्थकेयर



बीमारियों की पहचान और उपचार, नई दवाओं की खोज, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और आपरेशनल दक्षता बढ़ाने में एआइ की भूमिका बढ़ रही है। इससे आने वाले वर्षों में हेल्थकेयर सेक्टर में बड़ा बदलाव दिखेगा।

### मैनुफैक्चरिंग



प्रिडिक्टिव मेंटिनेंस से लेकर सप्लाई चेन को प्रभावी बनाने तक एआइ बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो रहा है। इससे क्वालिटी कंट्रोल के साथ-साथ क्षमता वृद्धि भी होगी।

### फाइनेंस



वित्तीय धोखाधड़ी के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे निपटने के लिए एआइ का प्रयोग किया जाने लगा है। इससे फ्राड डिटेक्शन, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, रिस्क असेसमेंट और डाटा आधारित निर्णय लेने में एआइ अब सार्थक भूमिका निभा रहा है।

### मार्केट



बाजार ट्रेंड को जानने-समझने, कैंपेन को आटोमेट करने और कंटेंट को अधिक उपयोगी बनाने में एआइ की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है।

### ट्रांसपोर्टेशन



लाजिस्टिक्स, आटोनामस व्हिकल और डाक्यूमेंटेशन में एआइ के अलग-अलग टूल्स प्रयोग किए जाने लगे हैं।

**Dainik Jagaran Page No-13**

लागत ज्यादा

# छोटे परमाणु रिएक्टरों की राह अभी भी रहेगी मुश्किल

**दायित्व कानून में संशोधन सकारात्मक, लेकिन भारत में उच्च लागत एक बड़ी अड़चन, अधिक समय लगने को भी बड़ी बाधा के तौर पर किया गया है चिह्नित**

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

लोकसभा से बुधवार को पारित सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट आफ न्यूक्लियर एनर्जी फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया (शांति) बिल, 2025 में भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की इच्छुक विदेशी कंपनियों की एक बड़ी मांग को स्वीकार करने का प्रविधान है, पर अभी भी विशेषज्ञ इस बात से संतुष्ट नहीं है कि इससे भारत में बड़ी संख्या में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जा सकेंगे। वजह यह है कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की लागत अभी भी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले या भारत में ही अन्य ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है।

भारत ने कई देशों की सरकारों के साथ छोटे माड्यूलर परमाणु रिएक्टर (एसएमआर) स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर विमर्श शुरू किया है, पर इन देशों ने यहां इस सेक्टर की उच्च लागत व काफी ज्यादा समय लगने को बड़ी बाधा के तौर पर चिह्नित किया है। इसी कारण किसी देश से अभी तक ठोस समझौता नहीं हो पाया है।



प्रतीकात्मक

इक्रा रेटिंग एजेंसी के वाइस-प्रेसिडेंट अंकित जैन का कहना है, 'निश्चित तौर पर इस विधेयक ने आपरेटरों की दायित्व सीमा को लेकर निजी क्षेत्र की मुख्य आशंका को दूर करने की कोशिश की है, पर कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे अत्यधिक उच्च पूंजीगत लागत, लंबी परियोजना अवधि व अन्य समस्याएं। निजी कंपनियों के पास इस क्षेत्र में परिचालन का कोई ट्रैक रिकार्ड नहीं है।' एक मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने में भारत में 18-20 करोड़ की लागत आती है। सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए लागत अधिकतम पांच करोड़ व ताप बिजली संयंत्रों के लिए 8-9 करोड़ रुपये है। सूत्रों के मुताबिक, पूर्व में जब अमेरिका व फ्रांस की कंपनियों संग भारतीय योजना पर बात हुई तो विदेशी कंपनियों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। फरवरी, 2025 में भारत-फ्रांस ने एसएमआर और एडवांस्ड माड्यूलर रिएक्टरों (एएमआर) पर साझेदारी के लिए घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के साथ भी पुराने असैन्य परमाणु समझौते के तहत एसएमआर पर चर्चा चल रही है। ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते में भारत में छोटे रिएक्टरों के आयात की संभावनाएं खुली हैं। लागत एक कारण है कि किसी देश संग परमाणु ऊर्जा सहयोग की बात बहुत आगे नहीं बढ़ पाई है। लागत बढ़ने का कारण भू-अधिग्रहण की भारी लागत व दूर-दराज क्षेत्रों में इनकी स्थापना को बताया जा रहा है। दुनिया में एसएमआर तकनीक के मामले में अमेरिका (नूस्केल जैसे डिजाइन), रूस (रोसाटाम), चीन (लिंगलांग वन), ब्रिटेन (राल्स-रायस), कनाडा व फ्रांस अग्रणी हैं। इन देशों में कई एसएमआर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट या डिप्लायमेंट स्टेज में हैं। भारत में 'भारत स्माल रिएक्टर' (बीएसआर) विकसित करने पर काम चल रहा है। वर्तमान में देश में परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता करीब 8,800 मेगावाट है, जिसमें 25 रिएक्टर विभिन्न संयंत्रों में कार्यरत हैं। सरकार ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को एक लाख मेगावाट तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। अल्पकालिक लक्ष्य के तहत 2032 तक क्षमता को 22,000 मेगावाट तक बढ़ाने पर जोर है।

********

**Dainik Jagaran Page No-3**

# बुरे फंसे आसिम मुनीर, आगे ट्रंप पीछे कट्टरपंथी

**जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली:** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं। इसकी वजह ट्रंप की गाजा योजना है, जिसके तहत गाजा में एक स्थिरीकरण बल की तैनाती होनी है। ट्रंप प्रशासन इस्लामाबाद पर इस बल में पाकिस्तानी सैनिकों को शामिल करने के लिए काफी दबाव बना रहा है। अगर मुनीर इसके लिए राजी होते हैं तो उन्हें घरेलू स्तर पर कट्टरपंथियों और जिहादियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और मना किया तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे। यह उनके लिए एक तरफ कुंआ और दूसरी ओर खाई वाली स्थिति है।

समाचार एजेंसी रायटर ने दो सूत्रों के हवाले से बताया कि आगामी हफ्तों में फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए वाशिंगटन जा सकते हैं। उनकी यह यात्रा गाजा बल पर केंद्रित होगी। छह महीने में उनकी यह तीसरी अमेरिका यात्रा होगी। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा, 'अगर पाकिस्तानियों ने इस मिशन का हिस्सा बनने से इन्कार किया तो यह ट्रंप को निराश कर सकता है। इससे पाकिस्तान के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि आसिम मुनीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का पूरा असैन्य और सैन्य नेतृत्व अमेरिका से निवेश और सुरक्षा सहायता चाहता है, जो लंबे समय से ठप है।' जबकि लेखिका और रक्षा विशेषज्ञ आयशा सिद्दीकी का कहना है कि ट्रंप की दिलचस्पी पाकिस्तान की सैन्य ताकत की वजह से है। हालांकि पाकिस्तानी सेना और विदेश मंत्रालय ने इस बारे में रायटर के सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है।

- गाजा में पाकिस्तान के सैनिकों की तैनाती के लिए पड़ रहा है भारी दबाव
- ऐसा कदम उठाया तो घरेलू स्तर पर झेलनी पड़ेगी जिहादियों की नाराजगी

आसिम मुनीर। फाइल >>

## डोनाल्ड ट्रंप से निकटता बना रहे मुनीर

अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में वर्षों तक अविश्वास वाली स्थिति रही। गत अप्रैल में ऐसी खबर आई कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अमेरिकी फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक समझौता किया है। इस अमेरिकी फर्म में ट्रंप के बेटे एरिक और ट्रंप जूनियर की हिस्सेदारी है। इसके बाद ही स्थिति बदली और पाकिस्तानी सेना प्रमुख ट्रंप के साथ निकटता बना रहे हैं। गत जून में उन्हें व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित किया गया था। इसके बाद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ व्हाइट हाउस का दोबारा दौरा किया था।

## ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली योजना

ट्रंप की 20 बिंदुओं वाली योजना में युद्ध के बाद संक्रमण काल में गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण और आर्थिक रूप से उबरने के दौरान मुस्लिम देशों से एक बल की तैनाती करने की बात है। यह फलस्तीनी क्षेत्र दो वर्ष से ज्यादा समय के दौरान इजरायली सेना की बमबारी से तबाह हो गया है। कई देश हमास के निरस्त्रीकरण करने के मिशन को लेकर सतर्क हैं कि वे संघर्ष में फंस सकते हैं और उनकी फलस्तीन समर्थक और इजरायल विरोधी आबादी नाराज हो सकती है। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम देश है, जो परमाणु हथियार से संपन्न है।

********

**Dainik Jagaran Page No-11**

# आइसीजी का पोत 'सार्थक' ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंचा

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) का अपतटीय गश्ती पोत 'सार्थक' खाड़ी देशों में चल रही विदेशी तैनाती के तहत मंगलवार को ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह पहुंचा। आईसीजी के अनुसार, यह चाबहार में किसी भारतीय तटरक्षक पोत की पहली यात्रा है, जो क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री भागीदारी को दर्शाती है।

आईसीजी ने बताया कि 'सार्थक' 19 दिसंबर तक चाबहार में रहेगा। इस दौरान ईरानी नौसेना और अन्य समुद्री एजेंसियों के साथ शिष्टाचार मुलाकातें, पेशेवर संवाद और संयुक्त गतिविधियां होंगी। इनमें समुद्री खोज-बचाव, समुद्री कानून प्रवर्तन और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया पर केंद्रित प्रशिक्षण शामिल है। चाबहार बंदरगाह में तेल तथा खतरनाक व हानिकारक पदार्थों (एचएनएस) के रिसाव से निपटने के लिए समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया जाएगा।

ओमान की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित चाबहार एक रणनीतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, जो भारत को ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा समुद्री मार्ग प्रदान करता है तथा पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले मार्गों का एक भू-राजनीतिक रूप से स्वतंत्र विकल्प है।

- पोत की पहली यात्रा है, जो क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री भागीदारी को दर्शाती है
- ईरानी नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ शिष्टाचार मुलाकातें होंगी

गश्ती पोत सार्थक। फाइल

**Dainik Jagaran Page No-11**

# अमेरिका से तीन और अपाचे हेलीकाप्टर मिले, जोधपुर स्क्वाड्रन में होंगे तैनात

- अमेरिकी दूतावास ने कहा-रक्षा साझेदारी को लेकर हमने प्रतिबद्धता निभाई
- भारत ने सेना के लिए बोइंग कंपनी से खरीदे हैं छह अपाचे हेलीकाप्टर
- वायु सेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकाप्टरों का बेड़ा है

नई दिल्ली में बुधवार को बोइंग एफ-64ई अपाचे हेलीकाप्टर की डिलीवरी लेते भारतीय सैन्य अधिकारी। एएनआइ

**Dainik Jagaran Page No-1**

संसद प्रश्नोत्तर

# शून्यकाल विपक्ष के लिए अवसर, 17 में 14 प्रश्न भाजपा के!

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में बुधवार को शून्य काल पर चर्चा के अंत में कांग्रेस सदस्य प्रमोद तिवारी ने सधे शब्दों में व्यवस्था पर ही प्रश्न खड़े करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि शून्य काल सामान्यतः विपक्ष को अपनी बात कहने का अवसर देता है। लेकिन, शायद यह इत्तेफाक ही है कि आज इस दौरान 17 प्रश्न उठाए गए, जिसमें से 14 भाजपा के थे। वह संकेतों में ही भेदभाव का संदेश देना चाहते थे, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तुरंत ही स्थिति स्पष्ट

प्रमोद तिवारी।

कर दी। शून्य काल के लिए प्रश्नों के चयन की व्यवस्था की और उनका ध्यान आकृष्ट कराया। सभापति ने संक्षेप में इतना ही कहा कि आप आकर ड्रा (लाटरी) की प्रक्रिया को देख सकते हैं।

Dainik Jagaran Page No-3

विकल्प

रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड एवं उत्तराखंड सहित 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दिया भारतपर्व में अपनी झांकी प्रदर्शित करने का विकल्प, हालांकि इस विकल्प को स्वीकार करना, न करना राज्यों की मर्जी

# कर्तव्य पथ पर न सही, भारत पर्व में मिलेगा झांकियों को मौका

संजीव गुप्ता • जागरण

नई दिल्ली : जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर शामिल नहीं हो पाएंगी, वो भारत पर्व का हिस्सा बन सकेंगी। रक्षा मंत्रालय ने ऐसे तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विकल्प भी उपलब्ध करा दिया है। गणतंत्र दिवस परेड के बाद कर्तव्य पथ वाली झांकियां भी भारत पर्व में प्रदर्शित की जाएंगी।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के ही एक हिस्से के रूप में हर साल लाल किला ग्राउंड में पांच दिवसीय भारत पर्व नामक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जाता है। यह पर्व 26 से 31 जनवरी तक चलता है, जहां देशभर की संस्कृति, व्यंजन, झांकियों और कला-शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। इसका उद्देश्य 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को बढ़ावा देना है।

लाल किला। फाइल

रक्षा मंत्रालय ने 77वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए कर्तव्य पथ पर 17 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी को स्वीकृति दी है। ऐसे में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बच गए या जिनकी झांकी का प्रस्ताव कर्तव्य पथ के लिए स्वीकार नहीं हो सका, उन सभी को रक्षा मंत्रालय की ओर से भारत पर्व में अपनी झांकी पेश करने का विकल्प दे दिया गया है। इनमें दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड भी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के न्योते या विकल्प को स्वीकार करना अथवा नहीं करना राज्य सरकारों की मर्जी पर है। कोई बाध्यता नहीं है।

सूत्रों के अनुसार कर्तव्य पथ से इतर भारत पर्व में झारखंड की झांकी देखने को मिल सकती है। हरियाणा इस पर विचार कर रहा है, वहीं दिल्ली सरकार ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत पर्व में हिस्सेदारी करने के नाम पर पीछे भी हट सकते हैं।

**रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत पर्व के लिए चयनित किए गए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश**

1. चंडीगढ़
2. दादर एवं नागर हवेली व दमनद्वीव
3. लद्दाख
4. अंडमान एवं निकोबार
5. अरुणाचल प्रदेश
6. बिहार
7. दिल्ली
8. गोवा
9. हरियाणा
10. झारखंड
11. कर्नाटक
12. तेलंगाना
13. त्रिपुरा
14. उत्तराखंड

********

Dainik Jagaran Page No-2

# ट्रंप ने सीरिया समेत सात और देशों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगाए

**वाशिंगटन, रायटर :** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पूर्ण यात्रा प्रतिबंध के दायरे में आने वाले देशों की सूची का विस्तार करते हुए सीरिया समेत सात और देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पूर्ण यात्रा प्रतिबंधित देशों की संख्या 19 हो गई है। इसके लिए ट्रंप ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया है।

मंगलवार को बर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान, सीरिया के नागरिकों और फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा जारी यात्रा दस्तावेजों के धारकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कार्रवाई के तहत लाओस और सिएरा लियोन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिन पर पहले केवल आंशिक प्रतिबंध लागू थे। अन्य 15 देशों अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, कोटे डी आइवर, डोमिनिका, गैबान, गांबिया, मलावी, मारिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जांबिया और जिम्बाब्वे को आंशिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले जून में ट्रंप ने 12 देशों अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो

- यात्रा प्रतिबंध का विस्तार फलस्तीनी प्राधिकरण पर भी लागू
- इससे पहले जून में 12 देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया था

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंध की घोषणा की थी। साथ ही बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला जैसे अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए थे।

## ट्रंप ने वेनेजुएला आने-जाने वाले प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकाबंदी का आदेश दिया

**वाशिंगटन, रायटर :** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वेनेजुएला में आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकाबंदी का आदेश दिया। यह निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए वाशिंगटन का नवीनतम कदम है।

यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रतिबंधित जहाजों के खिलाफ यह कार्रवाई कैसे करेंगे और क्या वे पिछले सप्ताह की तरह ही तटरक्षक बल की मदद लेंगे। प्रशासन ने क्षेत्र में हजारों सैनिक और लगभग एक दर्जन युद्धपोत तैनात किए हैं। इनमें एक विमानवाहक पोत भी शामिल है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हमारी संपत्तियों की चोरी और आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी सहित कई अन्य कारणों से वेनेजुएला सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया

- 2019 में अमेरिकी प्रतिबंध के बाद से तेल खरीदने वाले ऐसे बेड़े का सहारा ले रहे

गया है। इसलिए, आज मैं वेनेजुएला में आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूर्ण और व्यापक नाकाबंदी का आदेश दे रहा हूं।" एक बयान में, वेनेजुएला सरकार ने कहा कि उसने ट्रंप की धमकी को खारिज कर दिया है। ट्रंप की घोषणा के बाद अमेरिकी क्रूड वायदा एक प्रतिशत से अधिक चढ़कर 55.96 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया। मंगलवार को तेल की कीमतें 55.27 डालर प्रति बैरल पर बंद हुईं। 2019 में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर ऊर्जा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले व्यापारी टैंकरों के एक ऐसे बेड़े का सहारा ले रहे हैं जो अपनी लोकेशन छुपाते हैं।

**Dainik Jagaran Page No-11**

# इंडिया एआइ सम्मेलन ग्लोबल साउथ के लिए अवसर : भारत

**संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र :** भारत में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले 'एआइ इम्पैक्ट' शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों को एआइ एजेंडे को सक्रियता के साथ आकार देने का अवसर मिलेगा। इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने यह बात संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में कही।

नई दिल्ली में 19-20 फरवरी को होने वाले 'इंडिया-एआइ इम्पैक्ट समिट-2026' में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस भी हिस्सा लेंगे। पहली बार ग्लोबल साउथ के किसी देश में एआइ सम्मेलन होगा। इससे पहले बलेटचली पार्क (ब्रिटेन), सियोल और पेरिस में इस तरह के वैश्विक एआइ सम्मेलन हुए थे। यूएन में भारत और फ्रांस के स्थायी मिशनों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रसाद ने कहा, 'यह प्रतीकात्मक नहीं है। यह ठोस एवं सार्थक है। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश भविष्य में एआइ के उपयोगकर्ताओं,

- नई दिल्ली में 19-20 फरवरी को होगा यह सम्मेलन
- यूएन महासचिव गुटेरस भी सम्मेलन में होंगे शामिल

डाटा सृजन और उपयोग के मामले में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए उन्हें वैश्विक एआइ इकोसिस्टम को आकार देने में भूमिका निभानी चाहिए।' उन्होंने सभी हितधारकों को नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण देते हुए कहा कि यह एक ऐसा मंच है, जहां ग्लोबल साउथ केवल चर्चा का विषय नहीं बल्कि वैश्विक एआइ एजेंडा को सक्रिय रूप से आकार देता है।

देश-दुनिया की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

# बेंजामिन नेतन्याहू से मिले जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर की चर्चा

**▶ भारत- इजरायल की साझेदारी मजबूत होने का जताया विश्वास**

**▶ नेतन्याहू की प्रस्तावित भारत यात्रा की तैयारी के बीच जयशंकर का दौरा**

**यरुशलम, प्रेट्र :** विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने समेत द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। यह विश्वास जताया कि भारत-इजरायल की द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।

जयशंकर मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। जयशंकर ने अपने इजरायली समकक्ष गिदोन सार और उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ भी बातचीत की। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आज शाम यरुशलम में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं। प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, कौशल व प्रतिभा, संपर्क और सुरक्षा में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की।' उन्होंने कहा, 'क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर उनके विचारों को महत्व देते हैं। विश्वास है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।' नेतन्याहू ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर साझा कीं। जयशंकर का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब नेतन्याहू की प्रस्तावित भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं।

यरुशलम में इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ बैठक में चर्चा करते विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रेट्र

**Dainik Jagaran Page No-11**

# मोदी की मौजूदगी में भारत और ओमान के बीच आज होगा एफटीए

## तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी ओमान के मस्कट पहुंचे

**मोदी ने इथियोपियाई संसद को किया संबोधित, लोकतंत्र व सभ्यतागत संबंधों को सराहा**

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** भारत और ओमान गुरुवार को मस्कट में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, आटोमोबाइल, आटो कंपोनेंट्स, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में अधिक अवसर खुलेंगे। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में होगा। तीन राष्ट्रों की चार दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को मोदी इथियोपिया के अदीस अबाबा से ओमान के मस्कट पहुंच गए। वहां हवाई अड्डे पर उनका ओमान के उप प्रधानमंत्री, रक्षा मामलों के मंत्री सैयद शिहाब बिन तारीक अल सईद ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री को गार्ड आफ आनर दिया गया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस एफटीए हस्ताक्षर के लिए पहले ही मस्कट पहुंच चुके हैं। मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत, जिसे आधिकारिक रूप से सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) कहा जाता है, नवंबर 2023 में शुरू हुई थी और इस वर्ष समाप्त हुई। मुक्त व्यापार समझौतों में दोनों व्यापारिक साझेदार या तो अधिकांश वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को काफी कम करते हैं या उसे समाप्त कर देते हैं। वे व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए मानदंडों को भी सरल बनाते हैं। ओमान, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। ओमान पहुंचने से पहले मोदी ने अदीस अबाबा में इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इथियोपियाई संसद दुनिया की 18वीं संसद है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भारत और इथियोपिया क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपर्क में स्वाभाविक साझेदार हैं। मोदी ने दोनों देशों के लोकतंत्र और साझा सभ्यतागत संबंधों की सराहना की।

**▶ संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपर्क में भारत और इथियोपिया स्वाभाविक साझेदार**



मस्कट में बुधवार को ओमान के उप प्रधानमंत्री, रक्षा मामलों के मंत्री सैयद शिहाब बिन तारीक अल सईद से चर्चा करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। आइएएनएस

**ओमान का दो दशकों में पहला व्यापार समझौता**

वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल ने मस्कट में ओमान-भारत व्यापार मंच पर कहा कि यह ओमान का लगभग दो दशकों में पहला व्यापार समझौता होगा। ओमान ने जनवरी 2006 में अमेरिका के साथ एफटीए किया था। उन्होंने कहा कि "मुक्त व्यापार समझौता सभी के लिए विशाल अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ओमान में भारतीय निवेश 2020 से तीन गुना बढ़कर पांच अरब अमेरिकी डालर तक पहुंच गया है। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में लगभग 10.5 अरब अमेरिकी डालर था, जिसमें निर्यात चार अरब डालर और आयात 6.54 अरब डालर शामिल हैं। भारत के प्रमुख आयात में पेट्रोलियम उत्पाद और यूरिया शामिल हैं जोकि 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं।

मस्कट में बुधवार को होटल पहुंचने पर भारतीय सांस्कृतिक प्रस्तुति देखने के बाद कलाकारों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र



प्रधानमंत्री ने कहा- "इथियोपिया अफ्रीका के चौराहे पर स्थित है। भारत हिंद महासागर के दिल में है। हम क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और संपर्क में स्वाभाविक भागीदार हैं।" उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के रूप में, भारत और इथियोपिया एक-दूसरे से सीखने और देने के लिए तैयार हैं।। इथियोपिया दौरे के दौरान मोदी ने वहां के समकक्ष अबी अहमद अली से अर्थव्यवस्था, नवाचार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

## वंदे मातरम् की शानदार प्रस्तुति देख झूम उठे मोदी

पीएम मोदी ने बुधवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें इथियोपिया के तीन गायक भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गाते नजर आ रहे हैं। इस पर पीएम ने लिखा- "प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा आयोजित डीनर पार्टी में इथियोपियाई गायकों ने वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी। यह पल बहुत ही भावनात्मक है क्योंकि ये ऐसे समय में हुआ जब भारत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है।" मोदी यह शानदार प्रस्तुति देख झूम उठे और दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाने लगे।

बुधवार को मोदी ने इथियोपियाई संसद में 'वंदे मातरम्' और इथियोपिया के राष्ट्रीय गान (मार्च फारवर्ड, डियर मदर इथियोपिया) के बीच समानताएं खींचते हुए कहा कि दोनों देश अपनी भूमि को "मां" के रूप में दर्शाते हैं, जो उनके साझा दृष्टिकोण को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने संसद में फिर से सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रेट आनर निशान आफ इथियोपिया' से सम्मानित करने के लिए आभार व्यक्त किया।

अदीस अबाबा में बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र के लिए पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का खड़े होकर अभिवादन करते इथियोपियाई सांसद। प्रेट्र

## मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक : शाह

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलना "भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा" को दर्शाता है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है।

शाह ने मोदी को बधाई देते हुए कहा कि द ग्रेट आनर निशान आफ इथियोपिया" प्रधानमंत्री को विदेशी राष्ट्र द्वारा दिया गया 28वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, जोकि उनकी राजनैतिक कुशलता की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पुरस्कार मोदी के भारत-इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। मोदी को यह पुरस्कार मंगलवार को इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा अदीस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित विशेष समारोह में प्रदान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई देते हुए कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए देश के लिए गर्व का क्षण और भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति का प्रतीक बताया।

**Dainik Jagaran Page No-11**

# टैरिफ का हथियार के तौर पर हो रहा इस्तेमाल

## वित्त मंत्री ने कहा– हमें बढ़ते शुल्क से निपटने के साथ देश को समग्र आर्थिक मजबूती प्रदान करनी होगी

- हमें शुल्क का बादशाह बताने वाले ही इसका दुरुपयोग हथियार के तौर पर कर रहे
- भारत का इरादा कभी भी शुल्क का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने का नहीं रहा

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि शुल्क और अन्य उपायों के जरिये वैश्विक व्यापार का 'हथियार के तौर पर इस्तेमाल' तेजी से बढ़ता जा रहा है और भारत को ऐसे में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की समग्र मजबूती देश को अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी। वित्त मंत्री की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों के कारण वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है। मेक्सिको ने भी हाल ही में उन देशों पर उच्च शुल्क लगाने की घोषणा की है जिनके साथ उसके मुक्त व्यापार समझौते नहीं हैं।



नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ● प्रेट्र

यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि वैश्विक स्तर पर व्यापार स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा, 'शुल्क और अन्य कई उपायों के जरिये व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है। भारत को इसलिए सावधानीपूर्वक बातचीत करनी होगी और केवल शुल्क से निपटना काफी नहीं होगा बल्कि हमारी समग्र आर्थिक मजबूती ही हमें अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, 'भारत को यह कहकर उपदेश दिया जा सकता है कि आप (भारत) बहुत अंतर्मुखी हैं, आप शुल्क के बादशाह हैं इत्यादि। हालांकि शुल्क का दुरुपयोग हथियार के रूप में किया गया है।' मंत्री ने कहा कि भारत का इरादा कभी भी शुल्क का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने का नहीं रहा। सीतारमण ने कहा कि भारत ने केवल अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा की है ताकि वे ऐसे हालात से बच सकें जहां कोई देश या कंपनी अपने सस्ते सामान को बाजार में लाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मंत्री ने कहा कि आज व्यापार का हथियार के रूप में इस्तेमाल बिना किसी आलोचना के हो रहा है और कुछ देश कहते हैं कि शुल्क अच्छे नहीं हैं और किसी को भी यह कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि अचानक नए लोग सामने आकर कहते हैं कि हम शुल्क बाधाएं खड़ी करेंगे और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। इसलिए ऐसा लगता है कि यही नया सामान्य चलन बन गया है।

### केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य तय किए

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य तय किए हैं और अपने कर्ज के सतर को कम किया है। उन्होंने राज्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया ताकि देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना लक्ष्य हासिल कर सके। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने बजट तैयार करते समय पारदर्शिता के लक्ष्य तय किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय प्रबंधन सभी को दिखाई दे और जवाबदेही तय हो सके। उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि हम कोरोना के बाद जीडीपी के अनुपात में कर्ज को कम करने में सक्षम हुए हैं। बता दें कि कोरोना के बाद जीडीपी के अनुपात में कर्ज 61.4 प्रतिशत हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों से इसे 2023-24 तक 57.1 प्रतिशत तक लाने में मदद मिली। सरकार को उम्मीद है कि इस साल यह घटकर 56.1 प्रतिशत हो जाएगा।

### चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत रहेगी भारत की विकास दर : गीता गोपीनाथ

**नई दिल्ली, प्रेट्र :** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह अक्टूबर में आइएमएफ द्वारा अनुमानित 6.6 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोपीनाथ ने कहा कि आइएमएफ ने भारत की वृद्धि का अनुमान सरकार द्वारा जुलाई-सितंबर तिमाही की 8.2 प्रतिशत वृद्धि जारी करने से पहले लगाया था। उन्होंने कहा, 'अगर भारत 20 वर्षों तक लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखता है तो देश 2047 के विकसित लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि 20 साल तक लगातार आठ प्रतिशत की वृद्धि बनाए रखना आसान नहीं है और इसके लिए लगातार सुधारों की जरूरत होगी।

Dainik Jagaran Page No-10

# 200 शीर्ष उद्यमियों का कुल कारोबार 42 लाख करोड़

भारत के अपने दम पर कारोबार को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले 200 शीर्ष उद्यमियों का कुल कारोबार 2025 में 42 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले वर्ष यह वैल्यू 36 लाख करोड़ रुपये थी। आइडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट और हुरुन इंडिया सूची के अनुसार सूची में शामिल उद्यमियों के कारोबार में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे साफ है कि भारत के उद्यमी तेजी से पैसे वना रहे हैं।

₹1 लाख करोड़ या इससे अधिक वैल्यू वाली हैं पांच कंपनियां सूची में

53 नई कंपनियां और 102 नए फाउंडर जुड़े हैं 2025 की सूची में

47 कंपनियां हैं वित्तीय सेवाओं सेक्टर से

## देश के शीर्ष दस उद्यमी

| उद्यमी | कंपनी | कारोबार की वैल्यू (रुपये में) |
|---|---|---|
| दीपिंदर गोयल | इटरनल | 3.2 लाख करोड़ |
| राधाकिशन दमानी | एवेन्यू सुपरमार्ट्स | 3 लाख करोड़ |
| राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल | इंडिगो | 2.2 लाख करोड़ |
| अभय सोई | मैक्स हेल्थकेयर | 1.1 लाख करोड़ |
| श्रीहर्ष मजेटी और नंदन रेड्डी | स्विगी | 1.06 लाख करोड़ |
| दीप कालरा और राजेश मागो | मेकमाइट्रिप | 94,500 करोड़ |
| यशीष दाहिया और आलोक बंसल | पालिसी बाजार | 80,300 करोड़ |
| विजय शर्मा | पेटीएम | 72,900 करोड़ |
| फाल्गुनी नायर और अद्वैता नायर | नायका | 67,500 करोड़ |
| पीयूष बंसल और टीम | लेंसकार्ट | 67,000 करोड़ |



"उद्यमिता के लिए इकोसिस्टम की गुणवत्ता के लिहाज से भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। रिपोर्ट बिजनेस लीडर्स की असाधारण कहानियों का सम्मान करती है। ये उद्यमी देश के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं।

**विकास शर्मा,** हेड, वेल्थ मैनेजमेंट और प्राइवेट बैंकिंग, आइडीएफसी फर्स्ट बैंक






जागरण रिसर्च

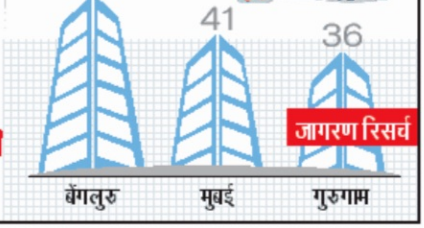

Dainik Jagaran Page No-10

मंथन

डा. सुनील कुमार मिश्र

एसोसिएट प्रोफेसर, विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, नई दिल्ली


# शिक्षा में भारतीयता की स्थापना

**विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में समयानुकूल परिवर्तन के साथ ही एक ऐसे शिक्षा आयोग का गठन करना है जो शैक्षणिक उन्नयन की पटकथा लिख सके**

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने का किया जा रहा प्रयास। फाइल

शिक्षा में भारतीयता स्थापित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान सत्र में लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है। 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक-2025' नामक इस विधेयक के जरिये सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मैकाले शिक्षा पद्धति के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त करने के संकल्प को पूरा करने में वह कोई कमी नहीं रखना चाहती है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाकर यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारत और भारतीयता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा में भारतीयता को स्थापित करने के लिए जो भी प्रयास करने होंगे सरकार द्वारा किया जाएगा। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक उसी प्रयास की दिशा में बढ़ाया गया सार्थक कदम कहा जा सकता है।

हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था उस राष्ट्र की दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करती है। राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी, वह उतनी ही तेजी से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा, क्योंकि शिक्षा ही वह महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्ति के समग्र जीवन को प्रभावित करने के साथ ही समाज एवं राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करती है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास का आधार रखने वाली शिक्षा व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र की उन्नति की संवाहक हो सकती है, ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्र की भावना के अनुरूप होना चाहिए।

विगत कुछ वर्षों से भारत विकसित राष्ट्र की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को समयानुकूल बनाना तर्कसंगत है, क्योंकि यदि हमें वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त करना है तो शिक्षा पद्धति में मौजूद कमियों को दूर करना होगा। आज जब वैश्विक शैक्षणिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है एवं सरकार वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उच्च शिक्षा के नियमन में बदलाव करना चाहती है तो हम सभी को मिलकर उसका स्वागत करना चाहिए।

प्रश्न यह उठता है कि भारत शिक्षा अधिष्ठान से शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होगा? तो यह समझना होगा कि इस अधिष्ठान के माध्यम से उच्च शिक्षा से जुड़ी यूजीसी, एआइसीटीई एवं एनसीटीई जैसी नियामक संस्थाओं को समाप्त करके एकल नियामक संस्था को आकार देने का प्रयास किया गया है। यह अधिष्ठान शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा जिससे संस्थान शिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार की दिशा में कार्य करने के लिए अधिक स्वतंत्र होंगे। इससे उच्च शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों के निर्धारण एवं समन्वय की प्रक्रिया आसान हो जाएगी जिससे संस्थान त्वरित गति से अपेक्षित कार्य कर सकेंगे।

हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एकल नियामक संस्था के रूप में यह अधिष्ठान पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार के साथ ही मानकीकरण एवं स्वायत्तता की प्रक्रिया आसान होगी एवं उच्च शिक्षण संस्थान नीति एवं पाठ्यक्रम को लेकर अधिक स्वतंत्र हो सकेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एकल शीर्ष निकाय के अस्तित्व में आने से उच्च शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा एवं विभिन्न नियामक संस्थाओं के मानकीकरण की लंबी प्रक्रिया से शिक्षण संस्थान को मुक्ति मिलेगी। हालांकि प्रस्तुत विधेयक में आइआइटी और आइआइएम जैसे कुछ महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों को इस अधिष्ठान से मुक्त रखा गया है जिससे उनकी स्वायत्तता बाधित न हो।

इससे स्पष्ट होता है कि सरकार शिक्षा में सुधार तो चाहती है, परंतु वह ऐसे किसी बदलाव से भी दूर रहना चाहती है जिससे राष्ट्रीय महत्व के किसी शैक्षणिक संस्थान का मार्ग अवरुद्ध हो। इस विधेयक के पारित होने से उन शैक्षणिक संस्थानों को एक लंबी मंजूरी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी जो कभी यूजीसी तो कभी एआइसीटीई जैसे नियामक संस्थानों से आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी होने का लंबा इंतजार करते थे। उदाहरणस्वरूप यदि कोई कालेज मानविकी एवं तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित करना चाहता था तो उसे यूजीसी एवं एआइसीटीई दोनों के निर्धारित मानकों को पूरा करके संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होती थी। यह विधेयक उच्च शिक्षण संस्थानों को ऐसी सभी जटिलताओं से मुक्ति प्रदान करेगा जिससे शैक्षणिक वातावरण में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

कहा जा सकता है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करने की दिशा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, राष्ट्रहित में बढ़ाया गया यह कदम सशक्त एवं समृद्ध भारत के सपने को साकार करेगा एवं भारत विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

**Dainik Jagaran Page No-9**

आजकल

अमित सिंह

उप नियंत्रक, पेटेंट एवं डिजाइन, पेटेंट कार्यालय, दिल्ली


# बौद्धिक संपदा कानून में व्यापक परिवर्तन

**भारतीय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने पिछले माह एक ऐसे ट्रेडमार्क आवेदन को स्वीकार किया, जिसमें दृश्य या शब्द के बजाय सुगंध को पहचान का आधार माना गया। सूंघने से संबंधित भारत के पहले ट्रेडमार्क की स्वीकृति संबंधित विधिशास्त्र के विकास में एक ऐतिहासिक मोड़ है और यह बौद्धिक संपदा संरक्षण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। यह ऐतिहासिक पंजीकरण इस बात का भी स्पष्ट संकेत है कि भारतीय ट्रेडमार्क व्यवस्था ब्रांडिंग, नवाचार और प्रौद्योगिकी की बदलती प्रवृत्तियों के साथ स्वयं को समायोजित कर रही है**

भारतीय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने पिछले माह एक ट्रेडमार्क आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जिसे सुगंध के लिहाज से विशिष्ट समझा जा रहा है। यह समाचार उन सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों और उनके संरक्षण पर निकटता से नजर रखते हैं, क्योंकि यह भारत का पहला घ्राण (सूंघने से संबंधित) ट्रेडमार्क एक्सेप्टेंस है, जो कि सुमितोमो रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान द्वारा दायर किया गया था। मामले की तह में जाने से पूर्व ट्रेडमार्क की अवधारणा को जानना आवश्यक है। किसी ट्रेडमार्क की प्राथमिक आवश्यकता यह है कि वह विशिष्ट हो और आपके माल या सेवाओं को अलग पहचान देने में सक्षम हो।

वर्तमान मामला एक अपरंपरागत (नान-ट्रेडिशनल) ट्रेडमार्क से संबंधित है और इसे समझने के लिए पहले इस प्रकार के चिह्नों का अर्थ जानना आवश्यक है। अपरंपरागत ट्रेडमार्क वे विशेष प्रकार के ट्रेडमार्क होते हैं जो केवल दिखने वाले संकेतों (लोगो या शब्दों) पर निर्भर नहीं होते। ये ट्रेडमार्क ध्वनि, गंध, स्वाद या स्पर्श जैसे अन्य इंद्रिय आधारित तत्वों का उपयोग करके ब्रांड की पहचान कराते हैं। उदाहरण के लिए, किसी एप को खोलते समय बजने वाली ध्वनि, किसी दुकान में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट खुशबू, ग्राहक को ब्रांड की पहचान करने में मदद करते हैं, भले ही वह उसे देख न रहा हो।

**अपरंपरागत ट्रेडमार्क की भूमिका** : आज के कड़े प्रतिस्पर्धा वाले और तेजी से बदलते बाजार में अपरंपरागत ट्रेडमार्क की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे-जैसे उपभोक्ता ज्यादा समझदार और चयनशील बन रहे हैं, कंपनियों भी अपने ब्रांड को यादगार और अलग पहचान देने के नए उपाय तलाश रही हैं। किसी ट्रेडमार्क आवेदन का निपटारा करने से पहले ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा उसकी जांच (एग्जामिनेशन) की जाती है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस मामले में आवेदक को सूचित किया गया कि आवेदन किया गया ट्रेडमार्क विशिष्टता (अलग पहचान) से रहित है, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो कि ट्रेडमार्क कानून के अंतर्गत एक अनिवार्य आवश्यकता है। यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि ट्रेडमार्क को कागज पर या डिजिटल रूप में इस तरह दिखाया जाए कि उसे देखा, समझा और पहचाना जा सके।

इस मामले में यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रेडमार्क सुगंध से संबंधित था। विशिष्टता के लिए आवेदक का यह तर्क था कि गुलाब की सुगंध इतनी विशिष्ट है कि जैसे ही 'गुलाब की गंध' का उल्लेख किया जाता है, आम जनता को तुरंत यह स्पष्ट हो जाता है कि वह गंध कैसी होगी। जब यह गंध टायर में होगी, तो सामान्य रबर की तेज और भारी गंध के स्थान पर फूलों की कोमल, सुगंधित और आकर्षक महक महसूस होगी और यही विशेषता इस टायर को सामान्य टायरों से विशिष्ट या अलग पहचान देती है। अनिवार्य ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन न होने की आपत्ति दूर करने के लिए आवेदक ने आइआइआइटी, इलाहाबाद में विकसित तकनीक का उपयोग करते हुए गुलाब जैसी गंध का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपनाया जिसमें इस गंध को एक वेक्टर के रूप में दर्शाया गया था।

ट्रेडमार्क आफिस ने यह माना कि यह रिप्रेजेंटेशन गुलाब जैसी गंध को पर्याप्त रूप से परिभाषित करता है और आवश्यकताओं का पालन करता है। इस मामले में अमीकस क्यूरी (न्यायालय के मित्र) के रूप में नियुक्त व्यक्ति ने कार्यवाही के दौरान रजिस्ट्री की सहायता हेतु प्रस्तुतियां दीं तथा ट्रेडमार्क की विशिष्टता को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप से स्थापित करने के लिए एक सहायक वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वैज्ञानिक, तकनीकी और कानूनी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेडमार्क को स्वीकार कर लिया गया है। यह ट्रेडमार्क पंजीकरण के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो तकनीकी समर्थन पर आधारित है और शब्द या डिवाइस चिह्नों की तरह नहीं है, जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है।

विश्व के कई देशों जैसे आस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में गंध चिह्नों को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकरण योग्य माना गया है। यह उल्लेखनीय है कि टेनिस बाल के लिए 'ताजी कटी हुई घास की गंध' को यूरोपीय ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया गया है। जब हम किसी दुकान में किसी खास ब्रांड को तलाशते हैं, तो यह उस ब्रांड के प्रति हमारे विश्वास और गहरे संबंध को दर्शाता है। अपरंपरागत ट्रेडमार्क, पारंपरिक ट्रेडमार्क से कहीं आगे बढ़कर स्पर्श, गंध जैसी इंद्रियों के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ एक अनोखे और अधिक मजबूत जुड़ाव बनाते हैं।

**एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर** : वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर सुगंध-आधारित ट्रेडमार्क को स्वीकार कर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने यह प्रदर्शित किया है कि वह ट्रेडिशनल मानकों से आगे बढ़कर विशिष्टता के निर्धारण हेतु आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए तत्पर है। अतः यह निर्णय भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रक्रिया की एक नई सुबह का प्रतीक है। यह कानूनी ढांचे और प्रौद्योगिकीय प्रगति के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। जैसे-जैसे नवाचार ब्रांडिंग की रणनीतियों को पुनर्परिभाषित करता रहेगा, यह ट्रेंड सेक्टर पंजीकरण तकनीकी रूप से उन्नत ट्रेडमार्कों की एक नई श्रेणी के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे देश में बौद्धिक संपदा संरक्षण की सीमा और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि होगी। यह निर्णय एक प्रगतिशील, प्रौद्योगिकी-प्रधान भविष्य की ओर अग्रसर ट्रेडमार्क कानून के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनकर उभरेगा।

## कानूनी अस्पष्टता के घेरे में सिंगल कलर ट्रेडमार्क

सिद्धार्थ मिश्रा

प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय


भारत में किसी एक रंग (सिंगल कलर) को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किए जाने का प्रश्न अब भी कानूनी अस्पष्टता की स्थिति में बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णय और कानून में स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है। यद्यपि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ परिस्थितियों में रंग आधारित ट्रेडमार्क को मान्यता मिली है, किंतु भारतीय ट्रेडमार्क कानून अब भी ऐसे चिह्नों की स्वीकार्यता को लेकर संघर्षशील बना हुआ है। इस संदर्भ में सबसे चर्चित उदाहरण है लक्जरी ब्रांड का प्रसिद्ध लाल सोल (रेड सोल), जो उनकी हाई-हील्ड जूतियों की विशिष्ट पहचान है। यह लाल सोल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड की विशिष्ट पहचान बन चुका है, किंतु भारत में इसे एकल रंग के ट्रेडमार्क के रूप में स्वीकार किए जाने का प्रश्न अभी भी अनसुलझा है।

इस कानूनी अस्पष्टता की जड़ वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दो विरोधाभासी निर्णय हैं। संबंधित मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि एकल रंग को ट्रेडमार्क नहीं माना जा सकता, क्योंकि ट्रेडमार्क अधिनियम के अंतर्गत 'रंगों के संयोजन' को ही चिह्न की श्रेणी में रखा गया है। न्यायालय के अनुसार, एकल रंग पर विशिष्ट अधिकार देना बाजार में एकाधिकार को बढ़ावा देगा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बाधित करेगा। हालांकि, इसी वर्ष एक अन्य मामले में उसी न्यायालय ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ भिन्न निर्णय दिया। इस मामले में न्यायालय ने माना कि लाल सोल 'अर्जित विशिष्टता' प्राप्त कर चुका है और उपभोक्ताओं के लिए यह ब्रांड की पहचान बन चुका है। अतः इसे संरक्षण दिया जाना चाहिए।

इन परस्पर विरोधी निर्णयों ने भारत में सिंगल कलर ट्रेडमार्क की वैधता को लेकर गहरी अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है। वर्तमान में ऐसे मामलों का निपटारा मुख्य रूप से मामले की परिस्थितियों और न्यायालय की व्याख्या पर निर्भर करता है, जिससे व्यापारिक संस्थाओं के लिए स्पष्ट दिशा का अभाव बना रहता है। उल्लेखनीय है कि किसी एक रंग को ट्रेडमार्क के रूप में संरक्षण प्राप्त करने हेतु दो प्रमुख शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। पहली, उस रंग ने इतनी विशिष्ट पहचान प्राप्त कर ली हो कि उपभोक्ता केवल रंग देखकर ही उस ब्रांड को पहचान सके। दूसरी, वह रंग उत्पाद की कार्यात्मक विशेषता न हो। यदि रंग उत्पाद की उपयोगिता या संरचना के लिए आवश्यक है, तो उसे ट्रेडमार्क के रूप में संरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे अन्य निर्माताओं की स्वतंत्रता प्रभावित होगी।

भारत में एकल रंग का ट्रेडमार्क पंजीकरण अत्यंत कठिन है। न्यायालय और प्राधिकरण इस विषय में अत्यधिक सतर्क हैं और ऐसे अधिकार देने से बचते हैं जो प्रतिस्पर्धा को सीमित कर सकते हैं। इसके विपरीत, रंगों के संयोजन को अधिक आसानी से संरक्षण मिल जाता है, विशेष रूप से जब वे विशिष्ट डिजाइन पैटर्न में प्रयुक्त होते हैं। हालांकि, हाल के समय में इस मामले में एक परिवर्तन देखने को मिला है। सुमितोमो रबर इंडस्ट्रीज द्वारा 'टायरों पर प्रयुक्त गुलाब की सुगंध' के लिए ओलफैक्टरी ट्रेडमार्क को स्वीकृति ने गैर-पारंपरिक ट्रेडमार्कों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी है। इस प्रगतिशील दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में सिंगल कलर ट्रेडमार्क के संबंध में भी अधिक स्पष्ट निर्णय सामने आएंगे।

यद्यपि वर्तमान में इस मामले में अस्पष्टता बनी हुई है, फिर भी यह स्पष्ट है कि भारतीय ट्रेडमार्क कानून धीरे-धीरे विकास की दिशा में अग्रसर है। वैसे इतना तो तय है कि आने वाले समय में ऐसे निर्णय भारत में ट्रेडमार्क संरक्षण की सीमाओं को पुनर्परिभाषित करेंगे और व्यापारिक जगत को अधिक स्पष्टता व स्थिरता प्रदान करेंगे।

**Dainik Jagaran Page No-9**

# हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण

**प्रदीप**

हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर चली आ रही बहस को एक नई दिशा मिली है। लंबे समय से पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए यह पहेली बनी हुई थी कि इतनी संगठित और तकनीकी रूप से विकसित सभ्यता कैसे धीरे-धीरे समाप्त हो गई। हाल ही में 'कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरमेंट' जर्नल में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार, इसकी वजह कोई अचानक आई प्राकृतिक आपदा, महामारी या आक्रमण नहीं थी, बल्कि सदियों तक चला जलवायु संकट था, जिसने इस सभ्यता की नींव को धीरे-धीरे कमजोर कर दिया।

हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे इसके शहर नियोजित सड़कों, पक्की नालियों, जल निकासी व्यवस्था और सुव्यवस्थित जल प्रबंधन के लिए आज भी शोधकर्ताओं को चकित करते हैं। इतने असाधारण विकास के बावजूद, लगभग 3,500 साल पहले इस सभ्यता में शहरी जीवन का धीरे-धीरे

**हड़प्पा सभ्यता का अंत एक झटके में नहीं हुआ। लंबे समय तक चली यह धीमी प्रक्रिया थी**

ह्रास शुरू हो गया। बड़े शहर सिकुड़ने लगे, व्यापारिक गतिविधियां कम होती गईं और लोग ग्रामीण इलाकों में बसने लगे। लंबे समय तक इस बदलाव के कारण स्पष्ट नहीं थे। हालिया अध्ययन में इसका कारण जलवायु संकट को माना गया है।

इस अध्ययन में विज्ञानियों ने जलवायु के दीर्घकालिक परिवर्तनों की ओर ध्यान केंद्रित किया। शोधकर्ताओं ने पांच हजार से तीन हजार साल पहले के बीच के मौसम और पर्यावरणीय परिस्थितियों का पुनर्निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने जलवायु माडलिंग के साथ-साथ गुफाओं में उपस्थित रासायनिक संकेतों तथा उत्तर-पश्चिम भारत की झीलों के जल-स्तर के आंकड़ों का सहारा लिया। इन सभी स्रोतों से जो छवि सामने आई, वह चिंताजनक है। इस पूरे कालखंड में औसत तापमान में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और वार्षिक वर्षा में 10 से 20 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई। इस अवधि में चार लंबे सूखे दौर आए, जो 85 वर्षों से ज्यादा वक्त तक चला। इन सूखों का प्रभाव हड़प्पा सभ्यता के 65 से 91 प्रतिशत हिस्से तक फैला हुआ था, जिसकी वजह से पानी की कमी व्यापक और निरंतर बनी रही।

इस जलवायु दबाव का असर लोगों की जीवनशैली पर पड़ा। साढ़े चार हजार वर्ष पहले तक लोग उन जगहों पर रहते थे जहां वर्षा अपेक्षाकृत ज्यादा होती थी। लेकिन जैसे-जैसे सूखे बढ़े, लोग सिंधु नदी के निकट बसने लगे। लगभग 113 वर्षों तक सूखा पड़ने का जब पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ अध्ययन किया गया तो शहरों के खाली होने और ग्रामीण बसावों के बढ़ने के संकेत मिलते हैं। यह अध्ययन आज के दौर के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी है। हड़प्पा सभ्यता का अनुभव दिखाता है कि यदि पर्यावरणीय दबाव लंबे समय तक बने रहे, तो सबसे संगठित और उन्नत समाज भी कमजोर पड़ सकते हैं। इतिहास से मिला यह सबक आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। **(लेखक विज्ञान संचारक हैं)**

**Dainik Jagaran Page No-8**

# विकसित बनेगा बिहार

बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय योजना-तीन को स्वीकृति देना राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। पिछले दो पंचवर्षीय कार्यकालों में लागू सात निश्चय-एक और दो ने राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया और विकास को गति दी। महिला और किसानों को सशक्त एवं सक्षम बनाया गया। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि में हुए सुधार ने आमलोगों के जीवन में ठोस बदलाव लाया है। अब सरकार ने अगले पांच वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखते हुए सात निश्चय-तीन की शुरुआत की है। इसमें दोगुना रोजगार और दोगुनी आय सबसे ऊपर है। एक करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौशल विकास और उद्योगों से मजबूत तालमेल जरूरी होगा। औद्योगिक विकास, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य जैसे निश्चय राज्य के समग्र विकास की बुनियाद हैं। परंतु उद्योग धंधों के मामले में बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है। इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर सात निश्चय-तीन बिहार के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी रोडमैप है। इसके प्रभावी ढंग से लागू होने का लाभ लंबे समय तक मिलेगा। चुनौती इसके ईमानदार और समयबद्ध क्रियान्वयन की है। इसलिए यह आवश्यक है कि योजना की घोषणा के साथ ही इसकी सतत निगरानी हो। संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई के प्रविधान भी किए जाएं। ऐसा किए जाने से विकास की दिशा में पिछले दो दशक से निरंतर अग्रसर बिहार तेजी से विकसित बनने की दिशा में प्रगतिशील है।

> विहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में सात निश्चय योजना-तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है

**Dainik Jagaran Page No-8**

उपलब्धि

अब मौसम के कारण जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद होने पर भी नहीं रुकेंगे सेना के कदम, जम्मू से स्पेशल मिलिट्री ट्रेन के जरिए अनंतनाग पहुंचा सेना का साजो-सामान

# ट्रेन के जरिये पहली बार सेना के टैंक पहुंचे कश्मीर

विवेक सिंह ● जागरण

**जम्मू:** भारतीय सेना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। युद्ध की स्थिति में अब देश के किसी भी हिस्से से बड़े टैंक, तोपखाने और इंजीनियरिंग उपकरण तुरंत कश्मीर में सीमा तक पहुंचाए जा सकेंगे। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसात, बर्फबारी, भूस्खलन या अन्य मौसम की चुनौतियों के बावजूद सेना की गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं आएगी। मंगलवार को विजय दिवस के अवसर पर सेना ने पहली बार स्पेशल मिलिट्री ट्रेन के जरिये जम्मू से अनंतनाग तक टैंक, भारी तोपखाने और अन्य सैन्य उपकरणों को सफलतापूर्वक पहुंचाया। यह कदम सीमाओं की रक्षा के लिए सेना की त्वरित तैनाती और आधुनिक व्यवस्था का एक बड़ा उदाहरण है।

पहले सेना के साजो-सामान को सड़क मार्ग से कश्मीर पहुंचाने में कई दिन लगते थे, जिसमें काफी मेहनत करनी पड़ती थी। भारी ट्रैफिक के कारण बड़े टैंक और तोपों को मंजिल तक पहुंचाना आसान नहीं होता था। लेकिन, अब ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक के माध्यम से सैन्य साजो-सामान का कश्मीर पहुंचाना एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि बन गया है। रेल से कश्मीर तक पहुंचने वाले टैंक और तोपों को अब सड़क मार्ग से कारगिल और लेह तक पहुंचाना भी आसान होगा। सीमांत क्षेत्र में नई सड़कें और पुलों के निर्माण से पहले ही सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है। सेना के साजो-सामान को रेलगाड़ी से कश्मीर पहुंचाने के ट्रायल के दौरान टैंक, आर्टिलरी गन और डोजर जैसे भारी सैन्य उपकरणों को सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया। यह ट्रेन रियासी जिले में बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल और देश के पहले केबल ब्रिज से भी गुजरी।

<< पहली बार जम्मू से कश्मीर तक तोपें, टैंक, सैन्य वाहन व उपकरण लेकर रियासी जिला में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च पुल से गुजरकर कश्मीर की ओर जाती रेलगाड़ी। सौ : सेना

### प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष छह जून को ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया था, जिससे कश्मीर आने-जाने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी लाभ मिल रहा है। अब देश के किसी भी हिस्से या राज्य से लोग सीधे रेलमार्ग से कश्मीर पहुंच सकते हैं।

### सेना की त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता को मिला बल : पीआरओ डिफेंस

रेल से साजो-सामान के कश्मीर पहुंचने से भारतीय सेना की त्वरित कार्रवाई करने की क्षमता को बल मिला है। सेना अब पूरे साल और हर मौसम में कश्मीर से देश के अन्य हिस्सों से जुड़ी रहेगी। कम समय में भारी सैन्य संसाधनों को कश्मीर घाटी या लद्दाख तक पहुंचा सकती है। इससे सेना की प्रतिक्रिया क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी।

Dainik Jagaran Page No-6

# गुलामी की मानसिकता छोड़ने की दिशा में कदम है 'परमवीर दीर्घा' : मोदी

- इस दीर्घा में सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए
- सरकार ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कई द्वीपों का नाम भी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे थे

**नई दिल्ली, एएनआइ :** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति भवन में 'परमवीर दीर्घा' का निर्माण गुलामी की मानसिकता त्यागने और देश को एक नई चेतना से जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस दीर्घा में सभी 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। वहां पहले ब्रिटिश एडीसी के चित्र प्रदर्शित थे।

मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राष्ट्रपति भवन की परमवीर गैलरी में देश के इन अदम्य नायकों के चित्र हमारे राष्ट्र के रक्षकों को हार्दिक श्रद्धांजलि हैं। वे नायक जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान से मातृभूमि की रक्षा की, जिन्होंने भारत की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए... राष्ट्र ने एक और तरीके से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है।

दो परमवीर चक्र विजेताओं और अन्य पुरस्कार विजेताओं के परिवारों की गरिमामय उपस्थिति में देश के परमवीरों की इस गैलरी को राष्ट्र को समर्पित करना, इसे और भी खास बनाता है।" उन्होंने याद दिलाया कि कुछ वर्ष पहले सरकार ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कई द्वीपों का नाम भी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे थे।

नरेन्द्र मोदी। फाइल

Dainik Jagaran Page No-5

# हेलीकाप्टर स्क्वाड्रन 'ओस्प्रे' नौसेना में शामिल

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रेट्र के अनुसार, गोवा स्थित आइएनएस हंसा नौसैनिक अड्डे पर एमएच-60आर (रोमियो) पनडुब्बी रोधी हेलीकाप्टरों का दूसरा स्क्वाड्रन-आइएनएएस 335 'ओस्प्रे' बुधवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की उपस्थिति में स्क्वाड्रन को नौसेना में शामिल किया गया। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक है।

**2015 में हुआ था पहली बार सौदा:** भारत-अमेरिका अपाचे डील का इतिहास 2015 में भारतीय वायुसेना के लिए 22 हेलीकाप्टर खरीदने से शुरू हुआ। इसके बाद 2020 में भारतीय सेना के लिए छह हेलीकाप्टर खरीदने का सौदा हुआ। इसके तहत इस साल जुलाई में तीन अपाचे हेलीकाप्टर भारत को मिले थे। बाकी तीन हेलीकाप्टर मंगलवार को पहुंचे। यह भारत की हवाई ताकत और दोनों देशों की रक्षा साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

**भारत को क्या रणनीतिक बढ़त मिलेगी :** यह हेलीकाप्टर चुनौतीपूर्ण और ऊंचे इलाकों में सेना की परिचालन और हमला करने की क्षमताओं को कई गुना बढ़ाएगा। यह खरीद सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अभियान का उद्देश्य आधुनिक युद्ध के लिए भारतीय सेना को तैयार करना है। यह हेलीकाप्टर शत्रु के ठिकानों, बंकरों और जटिल एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने में बहुत प्रभावी है। इस खरीद का मुख्य उद्देश्य सेना की स्वतंत्र उड्डयन क्षमता को मजबूत करना है, ताकि युद्ध या किसी भी सामरिक चुनौती के दौरान उसे सीधे ग्राउंड आपरेशन के लिए हवाई सहायता मिल सके।

### यह है अपाचे हेलीकाप्टर की खासियत

- अपाचे हेलीकाप्टर कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिनमें हवा से जमीन पर मार करने वाली हेलफायर मिसाइलें, 70 मिमी हाइड्रा राकेट और हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइलें शामिल हैं।
- इसे हवा में उड़ने वाला टैंक कहा जाता है। इसमें 1200 राउंड वाली 30 मिमी चेनगन भी लगी है, जो इसकी हथियार उपप्रणाली का हिस्सा है।
- हेलीकाप्टर में लांगबो फायर कंट्रोल रडार लगा है। अपाचे दुनिया का एकमात्र हमलावर हेलीकाप्टर है, जिसमें 360 डिग्री कवरेज देने वाला फायर कंट्रोल रडार है।
- लक्ष्य निर्धारण और नाइट विजन आपरेशन के लिए नोजल सेंसर सूट भी लगा हुआ है।
- एएच-64ई अपाचे का सबसे उन्नत संस्करण है। इसे मल्टी-डोमेन आपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है।

Dainik Jagaran Page No-5

# भारत में विदेशी विश्वविद्यालय बचा सकते हैं 113 अरब डालर

## रिपोर्ट में 2040 तक की संभावनाओं का किया गया है आकलन

**बदलते परिदृश्य में घटते राजस्व के बीच विकसित देशों के विश्वविद्यालय परिचालन के तरीकों में बदलाव पर कर रहे हैं विचार**

**50 % जीईआर 2035 तक पहुंचाने का लक्ष्य है, वर्तमान में जीईआर है 34%, 'ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आइ इंडिया आपर्च्युनिटी' की रिपोर्ट**

प्रतीकात्मक

**नई दिल्ली, प्रेट्र:** भारत में विदेशी विश्वविद्यालय 2040 तक 5.6 लाख छात्रों को शिक्षा देते हुए 113 अरब डालर की विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा इससे देश में 1.9 करोड़ वर्ग फीट रियल एस्टेट स्पेस की मांग भी पैदा हो सकती है। 'ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आइ इंडिया आपर्च्युनिटी' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में भारत के 40 शहरों की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट में दिल्ली-एनसीआर सबसे पसंदीदा बाजार के तौर पर उभरा है। बेंगलुरु इस मामले में दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय छात्र पारंपरिक रूप से घरेलू नामांकन पर इस गिरावट के दबाव को कम करने का काम करते रहे हैं, वहीं हाल के सालों में भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और बदलती कूटनीतिक प्राथमिकताओं के कारण यह गतिशीलता कमजोर हुई है, जिससे वीजा प्रतिबंध, सख्त इमिग्रेशन नीतियां और पढ़ाई के बाद काम के अधिकारों पर सीमाएं लगी हैं। "इन चुनौतियों के अलावा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग मेट्रिक्स का दबाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर विश्वविद्यालयों की फंडिंग, पार्टनरशिप और टैलेंट हासिल करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। डीकिन यूनिवर्सिटी (गिफ्ट सिटी), यूनिवर्सिटी आफ बोलोंगोंग (गिफ्ट सिटी) और यूनिवर्सिटी आफ साउथैम्प्टन (गुरुग्राम) ने यूजीसी के नियमों के तहत भारत में अपना बेस पहले ही बना लिया है। फिलहाल, कुल 18 विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए यूजीसी या आइएफसीएसए से सैद्धांतिक मंजूरी, तैयारी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। भारत में, अभी 5.3 करोड़ छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में हैं। इसके अलावा, 2024 में लगभग 7,60,000 छात्र इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में गए। इसके बावजूद भारत का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 34 प्रतिशत पर बना हुआ है, जो विकसित देशों में देखे जाने वाले 80 प्रतिशत और उससे ऊपर के स्तर से काफी कम है। केंद्र सरकार ने 2035 तक 50 प्रतिशत जीईआर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए कुल 7.2 करोड़ छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना होगा। वैश्विक पर सेक्टर की डिमांड के लिए यह चाहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित की अनुमति देती है।

Useful For Mains

# विकास के दावे और विषमता की खाई

**हाल में जारी वैश्विक असमानता रपट-2026 के अनुसार देश की कुल संपत्ति का 40 फीसद हिस्सा सिर्फ एक फीसद लोगों के हाथों में है, जबकि 65 फीसद संपत्ति दस फीसद लोगों के पास है। देश में आय के स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक है।**

अजय प्रताप तिवारी

देश की आर्थिक प्रगति ने समाज के कई समुदायों और वर्गों की भी उपेक्षा की है। दरअसल, विकास के क्रम में कतिपय वर्गों के हितों को साधने का प्रयास किया गया। इससे आर्थिक विकास के समक्ष लैंगिक असमानता, जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में असमानता, निर्धनता, जलवायु परिवर्तन तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। हाल में जारी वैश्विक असमानता रपट-2026 के अनुसार देश की कुल संपत्ति का 40 फीसद हिस्सा सिर्फ एक फीसद लोगों के हाथों में है, जबकि 65 फीसद संपत्ति दस फीसद लोगों के पास है। देश में आय के स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक है। कुल राष्ट्रीय आय की 58 फीसद हिस्सेदारी दस फीसद लोगों के पास है। जबकि पचास फीसद की हिस्सेदारी में 15 फीसद लोगों की भागीदारी है।

भारत में आय, संपत्ति और लैंगिक समानता में काफी अंतर देखने को मिलता है। महिला श्रम भागीदारी में भी निराशाजनक तस्वीर है। वहीं आज पूरी दुनिया में आर्थिक, लैंगिक और श्रम क्षेत्र में स्त्री-पुरुष विभेद बढ़ रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मगर जब बात लैंगिक समानता, श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और निर्धनता की आती है, तो मालूम होता है कि भारत वैश्विक मानकों पर बहुत पीछे है। देश में लैंगिक असमानता दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। विश्व आर्थिक मंच की ओर से जारी 'ग्लोबल जेंडर गैप रपट- 2025' में भारत 148 देशों में से 131 वें स्थान पर है। देश में राजनीतिक असमानता भी दिखाई देती है। वर्ष 2024 के चुनाव के बाद लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 13.6 फीसद है। वहीं स्थानीय सरकार में भागीदारी 44.4 फीसद है।

दुनिया भर में लड़कियां और महिलाएं आर्थिक असमानता की शिकार हो रही हैं। इस मसले पर अनेक रपटों में चिंता व्यक्त की गई है। भारत में अन्य देशों की अपेक्षा पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वेतन वाले काम कम मिलते हैं। देश के 119 अरबपतियों की सूची में मात्र नौ महिलाएं शामिल हैं। यदि विकास से जुड़े कार्यों की तुलना की जाए, तो महिलाएं 72 फीसद ही इसे हासिल कर पा रही हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 28 फीसद कम उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। आज दुनिया भर में 15 फीसद ऐसी महिलाएं हैं जो काम करने के योग्य हैं, लेकिन उनके पास काम के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। यदि पुरुषों की बात करें, तो यह आंकड़ा दस फीसद है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को काम करने के अवसर ज्यादा हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बात करें, तो वर्ष 2022 में 24.9 फीसद ने ही माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा हासिल की है। जबकि पुरुषों की यह संख्या 38.6 फीसद दर्ज की गई है।

भारत में विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग विषय में लगभग 43 फीसद महिलाएं स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रही हैं। यह आंकड़ा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ज्यादा है। मगर दुनिया भर में शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी अब भी बहुत कम है। भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। इसी तरह वर्ष 2012 से 2022 के बीच लगभग

44 फीसद युवा लड़कियां शिक्षा और रोजगार से वंचित रह गई थीं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा हो। निजी और सार्वजनिक उपक्रमों में महिलाएं बराबरी के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारत में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की अपार संभावनाएं हैं,

> **भारत में आय, संपत्ति और लैंगिक समानता में काफी अंतर देखने को मिलता है। महिला श्रम भागीदारी में भी निराशाजनक तस्वीर है। वहीं आज पूरी दुनिया में आर्थिक, लैंगिक और श्रम क्षेत्र में स्त्री-पुरुष विभेद बढ़ रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मगर जब बात लैंगिक समानता, श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और निर्धनता की आती है, तो मालूम होता है कि भारत वैश्विक मानकों पर बहुत पीछे है। देश में लैंगिक असमानता दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है।**

लेकिन इस क्षेत्र में भी महिलाएं बहुत पीछे हैं।

संयुक्त राष्ट्र भी मानता है कि अभी भी पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए संसाधन और तकनीकी पहुंच पुरुषों की अपेक्षा सीमित है। आज पूरे विश्व में 62 फीसद पुरुष इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वहीं 57 फीसद महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। डिजिटल तकनीक की सुलभता के मामलों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अब भी पीछे हैं। कई ऐसे कार्य हैं जहां महिलाओं की मेहनत का मोल नहीं है। आक्सफैम की रपट के अनुसार पूरी दुनिया में घरेलू कार्यों में लगी महिलाएं एक वर्ष में करीब दस हजार अरब डालर के बराबर काम करती हैं, जिसका उन्हें वेतन नहीं मिलता है। यदि इन महिलाओं के कार्यों की आर्थिक गणना की जाए, तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद करीब चार फीसद के बराबर होगा। कृषि कार्यों में जिस काम के लिए पुरुषों को अगर एक रुपया मिलता है, उसी काम को करने के लिए महिलाओं को 82 पैसे मिलते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी में लगभग 15 फीसद का अंतर है।

अगर श्रम बल आय की बात की जाए, तो यहां भी महिलाओं की भागीदारी महज 18 फीसद है जबकि पुरुषों का कुल श्रम बल आय 82 फीसद है। भारत में कुल व्यवसाय का लगभग 14 फीसद हिस्सा महिलाओं द्वारा संचालित होता है। वहीं केवल 17 फीसद महिलाओं को नियमित वेतन वाली नौकरी प्राप्त है। इक्यावन फीसद महिलाओं का कार्य अवैतनिक है। पनचानबे फीसद महिलाओं का कार्य अनौपचारिक और असंगठित है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से आर्थिक विकास की उन्नति होती है, गरीबी और भुखमरी घटती है।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, भारत में महिलाओं की आर्थिक विकास में भागीदारी बढ़ने से लगभग 4.5 करोड़ लोगों की भूख की समस्या से निजात मिलेगी। विश्व में लगभग दो सौ चालीस करोड़ महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और अवसर में पुरुषों के बराबर अधिकार से वंचित हैं। इस असमानता की खाई को कम करने में करीब 50 वर्ष या इससे अधिक वर्ष लग सकते हैं। आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 81.6 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा। भारत में आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने से काफी लाभ होगा। 'मेकिंस्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट' के अध्ययन के अनुसार, भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद 2.9 ट्रिलियन डालर की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। फिर भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बढ़ती असमानता संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। लोकतंत्र का मूल आधार सभी नागरिकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है, ऐसे में बढ़ती असमानता लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।

आर्थिक विकास में समान भागीदारी से नवप्रवर्तन, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी और अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों के सूचकांकों में बेहतरी आएगी। आर्थिक विकास में समान भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्तियों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार कौशल विकसित करना होगा और ज्ञान आधारित विकास पर जोर देना होगा, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था तकनीक और डिजिटल की ओर बढ़ रही है। देश में समान भागीदारी से न सिर्फ आर्थिक उन्नति बल्कि सकल घरेलू उत्पाद को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी। लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। निर्धनता घटेगी और खुशहाली बढ़ेगी। समावेशी समाज का निर्माण होगा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति समान भागीदारी के बिना संभव नहीं है।

Jansatta Page No-6

# आभार की शक्ति

अविनाश जोशी

हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां हर कोई तेजी से आगे बढ़ने की दौड़ में लगा है। पढ़ाई, नौकरी, करिअर और रिश्ते- हर जगह प्रतिस्पर्धा इतनी गहन हो गई है कि युवा पीढ़ी को असफलता, दबाव और असंतोष का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में आभार व्यक्त करने की आदत एक सामान्य-सी लग सकती है, लेकिन इसका असर असाधारण है। आभार जीवन की राह मोड़ सकता है, सोच की दिशा बदल सकता है और व्यक्ति को चक्र ऊर्जा दे सकता है, जिसकी तलाश वह हर जगह कर रहा होता है। आभार केवल किसी को धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक नजरिया है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में कितनी चीजें ऐसी हैं, जो हमें खुशी, सहयोग और समर्थन प्रदान करती हैं, तब हमारी दृष्टि समस्याओं से हट कर संभावनाओं पर केंद्रित हो जाती है। यह छोटा-सा बदलाव हमारे व्यक्तित्व में गहरी शांति और आत्मविश्वास जगाता है। युवा होने के नाते जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं। असफल परीक्षाएं, बेरोजगारी, टूटते रिश्ते या किसी सपने का पूरा न होना- ये सब परिस्थितियां युवाओं को हताश कर सकती हैं। मगर इन अनुभवों को एक आभारपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हर असफलता एक सबक बन सकती है।

आभार का लाभ यह है कि यह मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। जो युवा छोटी-छोटी उपलब्धियों या सहयोग के लिए धन्यवाद प्रकट करते हैं, उनके भीतर आत्मविश्वास और उम्मीद बनी रहती है। वे तनाव से जल्दी उबर जाते हैं और चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर पाते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध किया है कि कृतज्ञता का भाव रखने वाले लोग अवसाद से कम ग्रस्त होते हैं और जीवन को अधिक आनंदपूर्वक जीते हैं। रिश्तों में भी आभार का महत्त्व अत्यधिक है। युवा पीढ़ी के लिए मित्र और परिवार जीवन के हर कदम पर सहारा होते हैं, लेकिन व्यस्तता और तनाव के कारण अक्सर हम इसे भूल जाते हैं। एक साधारण-सा 'धन्यवाद' या स्नेहपूर्ण व्यवहार विश्वास को गहराई देता है। जब हम अपने माता-पिता, दोस्तों या शिक्षकों का आभार मानते हैं, तो उन्हें यह अहसास होता है कि उनकी भूमिका हमारे जीवन में कितनी मूल्यवान है। यह छोटा-सा कदम रिश्तों को और अधिक मजबूत बना देता है।

जीवन के बड़े व्यक्तित्व भी आभार की आदत को सफलता की कुंजी मानते रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि वे अपने विरोधियों तक के प्रति कृतज्ञ रहे, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनको सत्य और अहिंसा का महत्त्व अधिक गहराई से समझ आया। नेल्सन मंडेला ने जेल की कठिनाइयों को आभार की दृष्टि से देखा और उन्हें ताकत में बदल दिया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि आभार केवल आसान परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि विपरीत हालात में भी सहारा देता है। युवा पीढ़ी के लिए यह समझना भी आवश्यक है कि आभार केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी जरूरी है। जब कोई युवा अपनी मेहनत, अपनी कोशिशों और अपने साहस का सम्मान करना सीखता है, तो यह आत्मविश्वास से भर उठता है। स्वयं से आभार व्यक्त करना आत्म-विकास की दिशा में उठाया गया सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है। यह सोच हमें दूसरों से तुलना करने की आदत से दूर ले जाती है और हमें अपने मार्ग पर स्थिर रखती है।

आज की तेज रफ्तार दुनिया में अक्सर युवा अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे केवल बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और निराश हो जाते हैं, जब वे जल्द ही पूरे नहीं होते। ऐसे में आभार का अभ्यास यह सिखाता है कि हर छोटी सफलता, सहयोग और हर अवसर की महत्ता समझी जाए। यही दृष्टिकोण युवाओं को धैर्यवान और संतुलित बनाता है।

## दुनिया मेरे आगे

> **आज तेज रफ्तार दुनिया में अक्सर युवा अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और निराश हो जाते हैं, जब वे पूरे नहीं होते। ऐसे में आभार का अभ्यास यह सिखाता है कि हर छोटी सफलता, सहयोग और हर अवसर की महत्ता समझी जाए। यही दृष्टिकोण युवाओं को धैर्यवान और संतुलित बनाता है।**

आभार व्यक्त करना जीवन की कठिनाइयों को मिटा नहीं देता, लेकिन यह उनकी कठोरता को कम कर देता है। यह हमें यह देखने की क्षमता देता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा हुआ है। यही दृष्टिकोण जीवन की राह को मोड़ देता है। इसलिए युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि आभार केवल एक औपचारिकता या शिष्टाचार नहीं है, बल्कि एक जीवन-दर्शन है। यह न केवल हमें अंदर से मजबूत बनाता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यह जीवन को नई दिशा देता है, सपनों को उम्मीद से भरता है और हमारे समाज को अधिक सहयोगी और अधिक संवेदनशील बनाता है। युवाओं के लिए यह समझना आवश्यक है कि सफलता केवल पद और पैसे से नहीं, बल्कि संतोष और अच्छे रिश्तों से भी मापी जाती है। और संतोष तभी आता है, जब हम आभार की दृष्टि से जीवन को देखना सीख लें। यही दृष्टिकोण उन्हें आगे की कठिन राहों में आत्मविश्वास देगा, उनकी सोच को उजाले से भर देगा और उनकी जिंदगी को दिशा सही दिशा में मोड़ देगा।

Jansatta Page No-6

जानें-सीखें

# विकसित भारत शिक्षा बिल का क्या होगा असर

केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार और मानकीकरण लाने के उद्देश्य से विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इसे चर्चा और समीक्षा के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है ताकि विशेषज्ञ और शिक्षा जगत से सुझाव लिए जा सकें। इस विधेयक से विश्वविद्यालयों और कालेजों के संचालन में कौन-कौन से बदलाव आएंगे और शिक्षा प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए जानते हैं विस्तार से...

## उद्देश्य और मकसद

इस विधेयक के तहत सभी कालेज और विश्वविद्यालयों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई जाएगी। यह टीम तय करेगी कि कौन-से संस्थान अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और किनमें सुधार की आवश्यकता है। साथ ही यह निर्धारित करेगी कि संस्थानों को कितनी स्वतंत्रता मिले और किन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

## नियामक संस्थाओं का विलय

वर्तमान में अलग-अलग काम कर रहे तीन मुख्य नियामक संस्थाओं यूजीसी, एआइसीटीई और एनसीटीई को समाप्त कर एक एकीकृत उच्च शिक्षा नियामक संरचना बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य संस्थानों के संचालन, मान्यता और गुणवत्ता की निगरानी एक ही निकाय के माध्यम से करना है।

## तीन परिषदें और उनका काम

**नियामक परिषद** - संस्थानों के नियम और संचालन की निगरानी।

**मान्यता परिषद** - गुणवत्ता और मान्यता का मूल्यांकन।

**मानक परिषद** - शैक्षणिक मानक और छात्रों के सीखने के परिणाम तय करना।

## दंड और लागू संस्थान

संस्थानों द्वारा नियम उल्लंघन पर पहली बार 10 लाख रुपए, दोबारा उल्लंघन पर 30-75 लाख रुपए तक और बिना अनुमति नया विश्वविद्यालय खोलने पर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। यह कानून केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालय, आइआइटी, एनआइटी, अन्य कालेजों और आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा संस्थानों पर लागू होगा।

युवा शक्ति डेस्क

# 6जी तकनीक में हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे : सिंधिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि संचार की 5जी तकनीक के मामले में भारत की सफलता केवल देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की कहानी बन गई है। भारत 6जी में दुनिया का नेतृत्व करेगा।

सिंधिया ने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में 5जी तकनीक देश की ही नहीं, विश्वव्यापी सफलता की कहानी बन गई है। भारत ने 4जी में दुनिया का अनुसरण किया, 5जी में दुनिया के साथ चला और हम 6जी में विश्व का नेतृत्व करेंगे।

सिंधिया ने जनता दल (एकी) के दिलेश्वर कामैत के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि 2023 में 5जी का क्रियान्वयन शुरू होने से लेकर आज तक करीब पांच लाख बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) लग चुके हैं।

उन्होंने कहा कि देश के 778 जिलों में से 767 जिलों में 5जी उपलब्ध है। सिंधिया के मुताबिक आज देश में कुल मिलाकर 36 करोड़ 5जी उपभोक्ता हैं जिनकी संख्या 2026 तक बढ़कर 42 करोड़ और 2030 तक 100 करोड़ होने का अनुमान है।

Jansatta Page No-8

### वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा

# वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय किए

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अपने ऋण स्तर को कम किया है। उन्होंने साथ ही राज्यों से भी इन्हें लागू करने का आह्वान किया है।

सीतारमण ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 से राजकोषीय घाटे के साथ-साथ ऋण स्तर पर मुख्य तौर पर ध्यान दिया जाएगा। राज्यों को भी अपने ऋण स्तर को कम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि देश 2047 तक एक 'विकसित राष्ट्र' बनने के अपने लक्ष्य को हासिल कर सके।

*सीतारमण* ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 से राजकोषीय घाटे के साथ-साथ ऋण स्तर पर मुख्य तौर पर ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट तैयार करने में पारदर्शिता के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राजकोषीय प्रबंधन सभी के लिए पारदर्शी हो एवं जवाबदेही के उच्च मानकों को पूरा करे। परिणामस्वरूप, कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद से हम ऋण-जीडीपी अनुपात को कम करने में सक्षम हुए हैं। उस समय यह 60 फीसद से अधिक हो गया था। अब यह घटता हुआ प्रतीत हो रहा है।'

वैश्विक महामारी के बाद भारत का ऋण-जीडीपी अनुपात बढ़कर 61.4 फीसद हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों से इसे 2023-24 तक घटाकर 57.1 फीसद करने में मदद मिली। सरकार को उम्मीद है कि इस वर्ष यह घटकर 56.1 फीसद हो जाएगा।

ऋण-जीडीपी अनुपात, किसी देश के कुल कर्ज (सरकार व निजी) की उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से तुलना करने वाला एक महत्वपूर्ण आर्थिक पैमाना है।

Jansatta Page No-10

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा | उम्मीद | शिक्षकों की कमी को दूर करने पर भी दिया जोर

# उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तय करेगी वृद्धि की रफ्तार

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता क्षमता अगले 20 वर्षों में भारत के जनसांख्या संबंधी लाभांश को वृद्धि का इंजन बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

नागेश्वरन ने उद्योग मंडल 'सीआइआइ' की तरफ से उच्च शिक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि भारत में उच्च शिक्षा सुधार के अगले चरण की कुंजी राज्यों के पास है। उन्होंने शिक्षकों की कमी को तत्काल दूर करने की जरूरत पर जोर देते हुए उद्योग एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जैसे विकल्पों को अपनाने का सुझाव भी दिया। नागेश्वरन ने कहा कि राज्यों के लिए अन्य प्रमुख प्राथमिकताओं में प्रशासनिक नियंत्रण से आगे बढ़कर संरक्षण एवं मार्गदर्शन की भूमिका निभाना, इनपुट आधारित नियमन से हटकर परिणाम एवं गुणवत्ता पर आधारित नियमन, सार्वजनिक प्रशासन में उद्यमशील दृष्टिकोण अपनाना और संस्थानों को उनकी भूमिका एवं प्रदर्शन के आधार पर वित्तपोषण शामिल है।

*नागेश्वरन* ने उच्च शिक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि भारत में उच्च शिक्षा सुधार के अगले चरण की कुंजी राज्यों के पास है। उन्होंने शिक्षकों की कमी को तत्काल दूर करने की जरूरत पर जोर देते हुए उद्योग एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जैसे विकल्पों को अपनाने का सुझाव भी दिया।

सीईए ने कहा, 'भारत इस समय जनसांख्यिकीय और आर्थिक मुहाने पर खड़ा है। अगले दो दशकों में लाखों युवा कामकाजी उम्र में प्रवेश करेंगे। जनसंख्या का यह लाभांश आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देगा या सामाजिक दबाव का कारण बनेगा, यह काफी हद तक हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रासंगिकता पर निर्भर करेगा।'

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) ने सुधारों के लिए रास्ता खोला है और नियामकीय सोच में बदलाव आ रहा है, लेकिन अब जरूरत प्रभावी क्रियान्वयन, संस्थागत साहस और सहकारी संघवाद की है। उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण, शोध और शासन में उद्योग की गहरी भागीदारी का भी आ''न किया।

उन्होंने कहा कि उद्योग पाठ्यक्रम को मिलकर डिजाइन कर सकता है, क्रेडिट-आधारित इंटर्नशिप दे सकता है, अनुप्रयुक्त शोध में सहयोग कर सकता है और बुनियादी ढांचा साझा कर सकता है।

**Jansatta Page No-10**

लोकसभा में विपक्ष ने उठाए सवाल

# परमाणु ऊर्जा : निजी भागीदारी के विधेयक को मंजूरी

**जनसत्ता ब्यूरो**
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

लोकसभा ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्ष के विरोध के बीच बुधवार को मंजूरी प्रदान की।

सरकार ने 'भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025' को ऐतिहासिक करार दिया है तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें आपूर्तिकर्ता के उत्तरदायित्व का प्रावधान नहीं है तथा यह संवेदनशील क्षेत्र में निजी कारपोरेट समूहों के लिए रास्ता खोलने वाला है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा विधेयक पर चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद सदन ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए इसे ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो पहले भी थे, लेकिन सत्तापक्ष का विरोध करने के चक्कर में विपक्षी सदस्य अपने समय के प्रावधानों का विरोध कर देते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 37 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बजट है। मंत्री ने कहा कि यदि हमने 2047 तक 100 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य रखा है तो पूरा करने में परमाणु क्षेत्र महत्त्वपूर्ण है। सिंह ने कहा कि आज की दुनिया में अलग-थलग रहने का दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि उन्हीं सुरक्षा उपायों को जारी रखा गया है जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय अमल में आए थे।

*परमाणु* ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से विधेयक पर चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद सदन ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए इसे ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी।

सिंह ने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी, लेकिन सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया गया है। कुछ सदस्यों द्वारा 15 साल पहले भाजपा की ओर से अरुण जेटली द्वारा परमाणु ऊर्जा विधेयक के कुछ प्रावधानों का संसद में विरोध किए जाने का उल्लेख करने पर मंत्री ने कहा कि अब समय बदल गया है।

**Jansatta Page No-16**

शिक्षा मंत्रालय ने संसद में साझा किए आंकड़े | गिरावट | भारत में कुल 10.13 लाख सरकारी विद्यालय हैं

# पांच हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी ही नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 दिसंबर।

> *कोलकाता* में 211 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें नामांकन नहीं है और ये देश में दूसरा सबसे अधिक है। पूर्वी मेदिनीपुर में 177 और दक्षिण दिनाजपुर में 147 ऐसे स्कूल हैं, जहां नामांकन शून्य है। विद्यार्थियों की कमी के बावजूद इन संस्थानों में बड़ी संख्या में शिक्षक कार्यरत हैं। पूरे भारत में वर्तमान में 1.44 लाख शिक्षक ऐसे सरकारी विद्यालयों में तैनात हैं, जिनमें 10 से कम विद्यार्थी हैं या कोई नामांकन नहीं है। वर्ष 2022-23 में यह संख्या 1.26 लाख थी। आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में कम नामांकन वाले 6,703 सरकारी विद्यालयों में 27,348 शिक्षक तैनात हैं, जिससे हर विद्यालय में लगभग चार शिक्षक का अनुपात बनता है।

भारत में 10.13 लाख सरकारी विद्यालयों में से 5,149 विद्यालय में एक भी विद्यार्थी नहीं हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में जिन विद्यालयों में एक भी बच्चे ने नामांकन नहीं कराया, उनमें 70 फीसद से अधिक स्कूल तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में हैं। पूरे भारत में वर्तमान में 1.44 लाख शिक्षक ऐसे सरकारी विद्यालयों में तैनात हैं, जिनमें 10 से कम विद्यार्थी हैं या कोई नामांकन नहीं है। वहीं, आंकड़ों से यह भी पता चला कि 2019-20 से सरकारी विद्यालयों की संख्या में गिरावट आई है जो 10.32 लाख से घटकर 2024-25 में 10.13 लाख हो गई है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में संसद में साझा किए गए आंकड़ों से पता चला कि '10 से कम या शून्य नामांकन वाले' विद्यालयों में तीव्र वृद्धि हुई है। दो साल में ऐसे सरकारी विद्यालयों की संख्या में 24 फीसद की वृद्धि हुई है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में इन विद्यालयों की संख्या 52,309 से बढ़कर 2024-25 में 65,054 हो गई। सरकार ने लोकसभा सदस्य कार्ति पी चिदंबरम और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के प्रश्नों के लिखित उत्तर में कहा कि ये स्कूल अब देश के कुल सरकारी विद्यालयों का 6.42 फीसद हैं। तेलंगाना में लगभग 2,081 ऐसे स्कूल हैं, जिनमें नामांकन नहीं है जबकि पश्चिम बंगाल में ऐसे 1,571 संस्थान हैं। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में राज्य व देश में सबसे अधिक 315 खाली स्कूल दर्ज किए गए। महबूबबाद में 167 और वारंगल में 135 ऐसे स्कूल हैं, जहां नामांकन शून्य है। ये आंकड़े 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन प्लस' से प्राप्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 211 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें नामांकन नहीं है और ये देश में दूसरा सबसे अधिक है। पूर्वी मेदिनीपुर में 177 और दक्षिण दिनाजपुर में 147 ऐसे स्कूल हैं, जहां नामांकन शून्य है। विद्यार्थियों की कमी के बावजूद इन संस्थानों में बड़ी संख्या में शिक्षक कार्यरत हैं। पूरे भारत में वर्तमान में 1.44 लाख शिक्षक ऐसे सरकारी विद्यालयों में तैनात हैं, जिनमें 10 से कम विद्यार्थी हैं या कोई नामांकन नहीं है। वर्ष 2022-23 में यह संख्या 1.26 लाख थी। आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में कम नामांकन वाले 6,703 सरकारी विद्यालयों में 27,348 शिक्षक तैनात हैं, जिससे हर विद्यालय में लगभग चार शिक्षक का अनुपात बनता है।

**Jansatta Page No-16**

# 5,149 सरकारी स्कूल खाली

## किसे पढ़ा रहे हैं 1.44 लाख शिक्षक

वच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइकिल उपलव्ध कराने, मुफ्त भोजन देने व वुनियादी ढांचे में सुधार के वावजूद सरकारी स्कूल छात्रों को आकर्पित नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में पांच हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। इसके वावजूद इन स्कूलों में वड़ी संख्या में शिक्षक कार्यरत हैं।

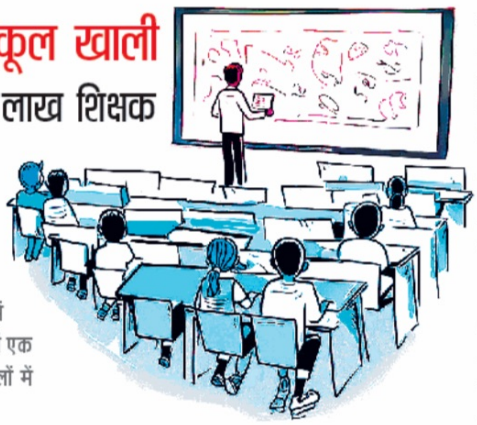



### सबसे ज्यादा खाली स्कूल बंगाल व तेलंगाना में

देश में 10.13 लाख सरकारी स्कूलों में से 5,149 स्कूलों में कोई छात्र नहीं है। 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में शून्य नामांकन दर्ज करने वाले इन स्कूलों में से 70 प्रतिशत से अधिक तेलंगाना और बंगाल में स्थित हैं। तेलंगाना में 2,081 स्कूल ऐसे हैं, जबकि बंगाल में ऐसे स्कूलों की संख्या 1,571 है।

**315** खाली स्कूल दर्ज किए गए हैं तेलंगाना के नालगोंडा जिले में, जो राज्य और देश में सबसे अधिक हैं

**167** महबूबबाद में और वारंगल में 135 ऐसे स्कूल हैं, जो तेलंगाना में सबसे अधिक संख्या वाले खाली स्कूलों में अगले दो जिले हैं

**211** शून्य नामांकन वाले सरकारी स्कूल हैं कोलकाता में

**177** पूर्वी मेदिनीपुर में और दक्षिण दिनाजपुर में 147 ऐसे स्कूल हैं, जो राज्य में दो सबसे अधिक संख्या वाले जिले हैं

**2022-23** में 52,309 से बढ़कर 2024-25 में 65,054 हो गई है 10 से कम या शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या देश में



### छात्रों की कमी लेकिन शिक्षकों की हाजिरी पूरी

छात्रों की कमी के बावजूद, इन संस्थानों में बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद हैं। मंत्रालय ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 2019-20 से सरकारी स्कूलों की संख्या में गिरावट आई है। 2024-25 में यह संख्या 10.32 लाख से घटकर 10.13 लाख हो गई है।

**1.44** लाख शिक्षक ऐसे सरकारी स्कूलों में तैनात हैं जिनमें 10 से कम छात्र हैं या कोई नामांकन नहीं है पूरे भारत में

**1.26** लाख थी ऐसे शिक्षकों की संख्या 2022-23 में

**27,348** शिक्षक नियुक्त हैं बंगाल में इस श्रेणी के 6,703 सरकारी स्कूलों में, यानी प्रति स्कूल औसतन चार शिक्षक

**3,600** शिक्षक तैनात हैं बिहार में ऐसे 730 स्कूलों के लिए, यानी प्रति संस्थान औसतन लगभग पांच शिक्षक

### तेजी से बढ़ी स्कूलों की संख्या

शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में संसद में साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 10 से कम या शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में पिछले दो वर्षों में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने लोकसभा में सांसदों कार्ति पी चिदंबरम व अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि ये स्कूल अब देश के कुल सरकारी स्कूलों का 6.42 प्रतिशत हैं।

(स्रोत : प्रेट्र)

**Dainik Jagaran Page No-5**

# विपक्ष के निशाने पर न्यायपालिका

**मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका को दबाव में लेने की ही कोशिश है**

उमेश चतुर्वेदी

सदियों पुरानी परंपरा का विरोध। फाइल

तमिलनाडु में जिस तरह कार्तिगई दीपम परंपरा स्थापित करने का आदेश देने वाले मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ द्रमुक और उसके सहयोगी दलों ने लामबंदी की, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि इस गठजोड़ के घटक बिहार के नतीजों से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। द्रमुक सांसद कनिमोई की अगुआई में आइएनडीआइए के 120 सांसदों द्वारा स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देना गठबंधन की पारंपरिक राजनीति का ही विस्तार है। गठबंधन यह पचा नहीं पा रहा कि किसी जज ने बहुसंख्यक सनातनी परंपरा स्थापित करने का निर्णय दे दिया। मदुरई जिले की तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी की चोटी पर कार्तिगई दीपम की परंपरा को स्थापित करने की मंजूरी दी, जिसे 1920 के एक विवाद के बंद कर दिया गया था। द्रमुक की अगुआई वाली तमिलनाडु सरकार ने विवाद की आशंका के बहाने स्वामीनाथन के फैसले को लागू ही नहीं होने दिया। दिलचस्प है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने इसका विरोध भी नहीं किया, बल्कि सरकार ने ही विवाद भड़काया।

राज्य सरकार ने स्वामीनाथन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की, लेकिन उसे यह भी लगा कि अगर उसने जज को सबक नहीं सिखाया तो सेक्युलरवाद की बुनियाद पर टिकी उसकी राजनीति में दरार पड़ सकती है। जज को सबक सिखाने और न्यायपालिका पर अंकुश लगाने के द्रमुक के इस कदम में सबसे हैरतअंगेज कदम है विपक्षी गठबंधन के अन्य घटकों का बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना। लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग प्रस्ताव पेश करते वक्त कनिमोई के साथ कांग्रेस नेताओं और अखिलेश यादव की मौजूदगी के संकेत गहरे हैं। विपक्षी दल अल्पसंख्यक समुदाय को यह संकेत देने की कोशिश में हैं कि सिर्फ आइएनडीआइए ही उसके हितों के लिए किसी जज को भी निशाना बना सकता है। विपक्षी गठबंधन की कोशिश कुछ महीने बाद होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की करीब छह प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी को लुभाना है। चूंकि द्रमुक की राजनीति के केंद्र में अल्पसंख्यकवाद का भी मंत्र रहा है, इसलिए कार्तिगई दीपम की परंपरा को रोकने में उसे कोई हिचक नहीं हुई।

इस पूरे मसले पर चर्चा से पहले जानना जरूरी है कि कार्तिगई दीपम त्योहार है क्या? दक्षिण के दीप पर्व के रूप में विख्यात कार्तिगई दीपम भगवान मुरुगन के सम्मान में तमिल महीने में दीप जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद को सुलझाने के लिए शिवजी स्वयं अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उसी स्तंभ की स्मृति स्वरूप उचिपिल्लायर मंदिर के पास प्राचीन दीपाथुन नामक स्तंभ के नजदीक महादीपक जलाया जाता है। तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर भी इसकी परंपरा रही, लेकिन बाद में वहां मंदिर के नजदीक एक दरगाह स्थापित हो गई। दरगाह के बाद सेक्युलरवाद को बढ़ावा देना जरूरी था, लिहाजा दीपम की परंपरा अधिकारियों ने रोक दी। इसे ही शुरू करने को लेकर अदालती हस्तक्षेप की मांग की गई। पहले मदुरई की जिला अदालत में मामला चला और बाद में मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने पहाड़ी पर दीप जलाने की परंपरा शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद पहाड़ी पर तीन दिसंबर को श्रद्धालुओं का जमावड़ा होने लगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। द्रमुक सरकार के इस दांव ने भाजपा को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। वह पूछ रही है कि आखिर राज्य के हिंदुओं ने कौन सी गलती की है कि उन्हें दीप जलाने के अधिकार के लिए अदालत का रुख करना पड़ा और वहां से अनुकूल आदेश मिलने के बाद भी उसका पालन नहीं होने दिया गया?

द्रमुक की पूर्ववर्ती जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में हुई थी। उसकी स्थापना ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए हुई थी। कालांतर में उसकी ब्राह्मणवाद विरोध की राजनीति बढ़ते-बढ़ते ब्राह्मण विरोध पर केंद्रित हो गई। बाद में उसके विरोध के दायरे में हिंदी और पूरी सनातन परंपरा समा गई। यही वजह है कि स्टालिन कुनबे को हिंदुत्व की कटु आलोचना से कभी परहेज नहीं रहता। अहर्निश हिंदी विरोध और अब कार्तिगई दीपम का विरोध इसी परंपरा का विस्तार है।

विपक्षी गठबंधन को इन दिनों संविधान बचाने की बहुत चिंता है। 'संविधान खतरे में है' की आवाज बुलंद करने वाले विपक्षी गठबंधन की नजर में न्याय वही है, जो उनके नैरेटिव के हिसाब से हो, अन्यथा वह सेक्युलरवाद का विरोध है। राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ये दल अब भी दिल से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इसी क्रम में अब स्वामीनाथन पर भी निशाना साधा जा रहा है। इसने एक बार फिर विपक्षी गठबंधन की अल्पसंख्यकपरस्त सियासी रणनीति का चेहरा उजागर किया है।

कोई सरकार किसी अदालती फैसले से असहमत है तो क्या उसका रास्ता महाभियोग है? एकल पीठ के विरुद्ध बड़ी पीठ का विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला था। इसके बजाय सीधे महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश से यही लगता है कि तमिलनाडु सरकार ऐसा माहौल बनाना चाहती है, जिससे आगे अदालतें उसके मनमाफिक ही फैसला दें। यह न्यायपालिका को दबाव में लेने की कोशिश है। यह कोशिश द्रमुक और उसके साथी दलों को महंगी पड़ सकती है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक समीक्षक हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

# बढ़ाया जाए सुधारों का दायरा

जीएन वाजपेयी

**जीडीपी की वृद्धि दर को आठ प्रतिशत से ऊपर ले जाने के अलावा हमें न्यायपालिका, सार्वजनिक प्रशासन और पुलिस में भी संस्थागत सुधार करने होंगे**

अवधेश राजपूत

विश्व आर्थिकी की दशा-दिशा बताने वाले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आइएमएफ के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अक्टूबर अनुमान के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का रुख कायम रह सकता है। इसमें जोखिम के पहलू बने हुए हैं। इसी पृष्ठभूमि में 28 नवंबर को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के आंकड़े चौंकाने वाले रहे। इस दौरान जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह इस कारण भी बड़ी उपलब्धि लगती है कि वैश्विक मंदी के साये और ट्रंप के टैरिफ से बनी अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज हो गई। पहली तिमाही में जीडीपी ने 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी।

दूसरी तिमाही के दौरान जीडीपी के प्राथमिक क्षेत्र कृषि में 3.5 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग में 7.7 प्रतिशत, विनिर्माण में 9.1 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र यानी सेवाओं में 9.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है। यही कारण है कि भारत लंबे समय से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वैसे इन आंकड़ों पर कुछ लोग संदेह भी जता रहे हैं। हालांकि ऐसे कुछ स्वर वास्तविकता को नहीं उलट सकते। कोविड महामारी के बाद से ही कायाकल्प और तेजी के मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था साल दर साल विश्लेषकों की कसौटियों पर खरी उतरती आई है। वित्तीय वर्ष 2024 में 9.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि को एक तबके ने आंकड़ों की बाजीगरी कहकर खारिज करते हुए आशंका जताई थी कि अगले साल जीडीपी नीचे आ जाएगी। ऐसे लोगों को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने 6.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर्ज की। इससे दो वर्षों की औसत जीडीपी वृद्धि 7.85 प्रतिशत हो गई, जो संदेह जताने वालों के दावों को निस्तेज करती है।

अगर वर्ष 2000 से ही जोड़ें तो भारत की दीर्घकालिक जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत रही है। स्पष्ट है कि भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि सात प्रतिशत से अधिक हो गई है। ऐसे अनुमान के पीछे पिछले एक दशक के दौरान केंद्र सरकार के सुधार और विभिन्न सकारात्मक पहल प्रमुख आधार हैं। अगर वृहद आर्थिक सुधारों की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बिखराव को दुरुस्त करते हुए उसे जीएसटी के रूप में सशक्त किया गया है। इसी आर्थिक कड़ी में विधायी मोर्चे पर इनसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आइबीसी, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) और मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) जैसे कदम भी अहम रहे हैं। इस क्रम में बैंकों और कंपनियों के बहीखातों की सेहत सुधारी गई है। डिजिटल खाई को पाटने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना हुई है।

राजस्व खर्च की प्रधानता पर उस पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई, जिसने बुनियादी ढांचा निर्माण को गति प्रदान की। राजकोषीय घाटे पर काबू पाने में भी उत्तरोत्तर सफलता मिलती गई। याद रहे कि वर्ष 2013 में भारत को पांच सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, जो मुद्रास्फीति से लेकर राजकोषीय घाटा और अन्य अनेक मानदंडों के मामले में संघर्ष कर रही थीं, लेकिन सुधारों की निरंतर सौगात ने हालात बदलने के काम किए हैं।

बीते एक दशक में केंद्र सरकार की कई सकारात्मक पहल के भी अब फल मिलने लगे हैं। लखपति दीदी, मुद्रा ऋण, किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ इस मामले में उल्लेखनीय हैं। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक लखपति दीदी की संख्या एक करोड़ पहुंच गई है। इसके लिए तीन करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है। मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ ऋणों के माध्यम से 33 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी हुई है। ई-नैम के रूप में इलेक्ट्रानिक व्यापार पोर्टल देश भर के किसानों और कृषि उत्पाद विपणन समितियों के बीच सेतु बनकर एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के रूप में स्थापित हुआ है। ऐसी पहल कौशल विकास, रोजगार सृजन, क्षमता निर्माण और बाजार में स्थायित्व लाने में उपयोगी साबित हुई हैं।

आर्थिक मोर्चे पर वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी इस समय की एक बड़ी सफलता है। भारत ऐसी इकाइयों का गढ़ बनता जा रहा है। वर्तमान में 1,700 जीसीसी सक्रिय हैं, जो 19 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। इनके जरिये 2024 तक 64.6 अरब डालर का राजस्व सृजित हुआ। अनुमान है कि 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 100 अरब डालर तक हो सकता है। इसी बीच 'जन विश्वास' जैसे कदम जैसे आत्म-प्रमाणन एवं आत्म-मूल्यांकन के प्रविधान करते हैं। कई प्रविधान आपराधिक दायरे से बाहर हुए हैं। बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंडों द्वारा जन के धन की वापसी के लिए दबाव और कर प्राधिकरण आदि के स्तर से भी यही संकेत उभर रहे हैं कि धीरे-धीरे ही सही शासन की दृष्टि में सुधार हो रहा है। ये कदम बढ़ती आर्थिक भागीदारी, बेहतर बुनियादी ढांचे, घटती लाजिस्टिक्स लागत, आर्थिक उत्पीड़न में कमी और बढ़ते पूंजी उत्पादन अनुपात में रूपांतरित हो रहे हैं। हाल में घोषित श्रम सुधारों और गौबा समिति की सिफारिशों से स्थितियां और सुधर सकती हैं। इससे एमएसएमई को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। यह सही है कि इन सुधारों को 1991 के क्रांतिकारी सुधारों जैसी संज्ञा नहीं दी जा सकती, लेकिन यह तय है कि ये छोटे-छोटे सुधार बड़ी सफलता का आधार बनेंगे।

देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता यही है कि जीडीपी की वृद्धि दर लंबे समय तक आठ प्रतिशत से ऊपर ही रहे। इसके अलावा हमें न्यायपालिका, सार्वजनिक प्रशासन और पुलिस में भी संस्थागत सुधार करने होंगे। भूमि सुधारों को लेकर सहमति बनानी होगी। उद्यम अनुज्ञप्तियों पर अमल में लगने वाले समय और लागत में कमी, भूमि अधिग्रहण और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुगमता के लिए लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8